● वर्ष-6
● अंक-94
रायपुर, सोमवार
16 नवंबर 2026
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.

|| संगछध्वम् संवदध्वम् ||

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार



पेज-7>> अमेरिका में बढ़ेगा भारतीय...

बस्तर में बंदूक की जगह खेल के मैदान, भय और हिंसा की जगह विश्वास एवं विकास का नया वातावरण: नितिन

जनजातीय समाज का सम्मान, स्वाभिमान और समृद्धि हमारी सरकार का संकल्प : मुख्यमंत्री साय



धर्मजयगढ़। भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती पर रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ स्थित ऐतिहासिक दशहरा मैदान में राज्यस्तरीय जनजातीय गौरव दिवस समारोह का भव्य आयोजन हुआ। हजारों की संख्या में जनजातीय समाज के लोग शामिल हुए। समारोह में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया, वहीं मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने किसानों के हित में बड़ा फैसला सुनाया। राज्यसभा सांसद और और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि उनकी हार्दिक इच्छा इस ऐतिहासिक आयोजन में प्रत्यक्ष रूप से शामिल होने की थी, लेकिन प्रतिकूल मौसम के कारण वे उपस्थित नहीं हो सके। उन्होंने कहा कि बस्तर के जिन क्षेत्रों में कभी बंदूकों की आवाज सुनाई देती थी, वहाँ आज खेल के मैदान तैयार हो रहे हैं। बच्चे और युवा शिक्षा, खेल तथा कौशल के माध्यम से अपने सपनों को नई उड़ान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब बंदूक की जगह खेल का मैदान लेता है, हिंसा की जगह शिक्षा लेती है और भय की जगह विश्वास पैदा होता है, तब उस क्षेत्र के विकास को कोई रोक नहीं सकता। आज बस्तर के युवा इसी सकारात्मक परिवर्तन के प्रतीक बन रहे हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2024 में बस्तर ओलंपिक में डेढ़ लाख से अधिक प्रतिभागियों की भागीदारी रही। वहीं शैक्षणिक सत्र 2025-26 में प्रदेश के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के 408 विद्यार्थियों ने नीट तथा लगभग 346 विद्यार्थियों ने जेईई मेन्स में सफलता प्राप्त की। नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनजातीय समाज के सम्मान, सशक्तिकरण और विकास को राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में प्रमुख स्थान दिया है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान और लगभग 24 हजार करोड़ रुपये के प्रावधान वाली पीएम-जनमन योजना के माध्यम से जनजातीय बहुल गाँवों में आवास, सड़क, बिजली, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका के अवसरों का विस्तार किया जा रहा है।

बस्तर में शांति का नया सवेरा

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में नक्सलवाद के विरुद्ध अभियान को महत्वपूर्ण सफलता मिली है। बस्तर के दूरस्थ क्षेत्रों में शांति, सुरक्षा और विकास का नया वातावरण निर्मित हुआ है। मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान के अंतर्गत लगभग 35 लाख लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया है। मनेंद्रगढ़ और गीदम में नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की दिशा में कार्य किया जा रहा है।



प्रदेश में धान खरीदी प्रारंभ, 360 नए उपार्जन केंद्रों के साथ कुल संख्या बढ़कर हुई 3,100

मुख्यमंत्री ने समारोह में किसानों के हित में राज्य सरकार के महत्वपूर्ण निर्णय की जानकारी देते हुए कहा कि अब प्रति एकड़ निर्धारित अधिकतम 21 क्विंटल से कम धान बेचने वाले पात्र किसानों को भी पूरी आदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी। कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को प्रति एकड़ 13,839 रुपये की आदान सहायता राशि मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज 15 नवंबर से प्रदेशभर में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए धान खरीदी प्रारंभ हो गई है। किसानों की सुविधा के लिए राज्य सरकार ने 360 नए धान उपार्जन केंद्र प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही प्रदेश में धान खरीदी केंद्रों की कुल संख्या बढ़कर 3,10 हो गई है।



पिछली सरकारों ने न आदिवासियों को समझा और न ही उनकी परवाह की

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि नक्सल हिंसा का सबसे ज्यादा नुकसान आदिवासी समाज को ही उठाना पड़ा है। भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती पर मनाए जा रहे जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर वे महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में आयोजित कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, आदिवासियों के अधिकार छीन लिए गए और सब चुप रहे। उन्हें वोट देने तक की इजाजत नहीं थी, लेकिन उस समय की सरकारें चुपचाप सब देखती रहीं और आंखें बंद कर लीं। आज जब नक्सलवाद का खात्मा हो चुका है, तो आदिवासी समाज की माताएं और बहनें हमें अपना आशीर्वाद दे रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने न तो आदिवासी समुदायों को समझा और न ही उनकी परवाह की।

देश की दो बड़ी उपलब्धियों का किया जिक्र- प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज भारत नक्सलवाद और माओवाद से मुक्त हो चुका है, जिससे सबसे ज्यादा प्रभावित रहे आदिवासी समुदाय अब देश को अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। उन्होंने कहा, आज पूरी दुनिया में भारत की दो बड़ी उपलब्धियों की चर्चा हो रही है। पहली उपलब्धि देश के लोगों को बहुत ज्यादा गरीबी से बाहर निकालना है और दूसरी उपलब्धि देश को नक्सलवाद और माओवादी आतंक से मुक्त करना है। गरीबी दूर करने के प्रयासों पर बात करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी के बाद लोगों को घोर गरीबी से बाहर निकालना भारत की सबसे बड़ी सफलताओं में से एक है।

पीएम मोदी ने कहा कि आदिवासी समाज ने हमेशा अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई है। उनकी सरकार ने उन आदिवासी इलाकों के विकास के लिए ठोस काम किए हैं, जहां लंबे समय से जरूरी सुविधाओं की कमी थी।

बस्तर की दिवाली और विकास का नया दौर- प्रधानमंत्री ने बताया कि कुछ ही दिन पहले उन्होंने छत्तीसगढ़ के बस्तर के बीचों-बीच सुरक्षा बलों के साथ दिवाली मनाई, जो कभी ऐसा इलाका था जहां लोग जाने से भी डरते थे। उन्होंने कहा कि अब गढ़चिरौली समेत सभी नक्सल प्रभावित इलाकों में दिवाली के दीयों के साथ-साथ उम्मीद की एक नई किरण भी पहुंची है।

शाह का राहुल पर हमला: कहा-

भारत को बदनाम करने से सत्ता नहीं मिलेगी

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने रविवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में भारत, उसके लोकतांत्रिक संस्थानों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास कार्यों को बदनाम कर रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी को समझना चाहिए कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत को बदनाम करने से उन्हें सत्ता नहीं मिलेगी।



उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी सत्ता में वापस आना चाहते हैं, तो उन्हें विदेश जाना बंद करना होगा। उन्हें भारत के गांवों में जाना शुरू करना चाहिए। अमित शाह पुणे में राष्ट्रीय भारी इंजीनियरिंग सहकारी क्षेत्र को फिर से खड़ा करने की पहल की आधारशिला रखने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लगातार चुनाव हार रही है। इसी निराशा में पार्टी अंतरराष्ट्रीय मंचों पर देश और उसके नेतृत्व को निशाना बना रही है।

शाह ने 13 और 14 नवंबर को हैदराबाद में हुए भारत सम्मेलन पर भी तंज कसा। इस कार्यक्रम का आयोजन कांग्रेस के नेतृत्व वाली तेलंगाना सरकार ने किया था। उन्होंने कहा कि इसमें देश और विदेश से वामपंथी विचारधारा को बढ़ावा देने वाले लोगों को बुलाया गया था।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय प्रमुख समाचार

129 वेबसाइटों पर लगा बैन का मामला पीएमओ पहुंचा, दूरसंचार विभाग के सचिव तलब

नई दिल्ली। अदालती आदेशों के आधार पर 129 ऑनलाइन गैंबलिंग वेबसाइटों को ब्लॉक करने का मामला सामने आने के बाद पीएमओ ने दूरसंचार विभाग के सचिव को तलब किया।

उनसे पूछा कि सरकारी स्तर पर इतनी बड़ी चूक कैसे हुई और आदेशों की जांच किए बिना वेबसाइटों को बंद करने के निर्देश क्यों जारी किए गए। यह मामला इलाहाबाद और राजस्थान हाई कोर्ट के नाम से भेजे गए नकली आदेशों से जुड़ा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जालसाजों ने दस्तावेजों को असली दिखाने के लिए उन पर हाईकोर्ट का लोगो, मुहर और क्यूआर कोड तक लगा दिए थे।



उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद पुणे एयरपोर्ट पर वापस लौटी फ्लाइट

पुणे। महाराष्ट्र के पुणे एयरपोर्ट पर रविवार सुबह इंडिगो की एक फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। पुणे से गुवाहाटी जा रही फ्लाइट संख्या 6E 0623 ने उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही तकनीकी खराबी के कारण वापस पुणे एयरपोर्ट पर लैंडिंग की।

राहत की बात यह रही कि इस दौरान किसी भी तरह का बड़ा हादसा नहीं हुआ। मिली जानकारी के मुताबिक, इंडिगो की फ्लाइट 6E 0623 ने रविवार सुबह पुणे से गुवाहाटी के लिए उड़ान भरी थी। उड़ान भरने के बाद विमान का लैंडिंग गियर वापस अपनी जगह पर अंदर नहीं मुड़ पाया। इस तकनीकी दिक्कत का पता चलते ही सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विमान को तुरंत पुणे एयरपोर्ट पर वापस उतारने का फैसला लिया गया। इस विमान में कुल 192 लोग सवार थे।

इमरजेंसी लैंडिंग के बाद सभी यात्रियों और क्रू सदस्यों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। इस घटना में किसी के भी घायल होने की कोई खबर नहीं है। लैंडिंग गियर विमान के पहियों और उनसे जुड़े पूरे सिस्टम को कहा जाता है। इसका इस्तेमाल विमान को रनवे पर सुरक्षित उतारने और जमीन पर चलाने के लिए किया जाता है।

मोदी से मिले रिंकू सिंह: शादी में आने का दिया निमंत्रण

नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह ने समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज के साथ होने वाले अपने विवाह के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया है। शादी से पहले रिंकू ने पीएम मोदी से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया। रिंकू ने अपने परिवार के साथ प्रधानमंत्री से मुलाकात कर व्यक्तिगत रूप से उन्हें निमंत्रण दिया।

मुलाकात की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा करते हुए रिंकू ने अपनी कृतज्ञता व्यक्त की और इसे अपने परिवार के लिए एक विशेष क्षण बताया।

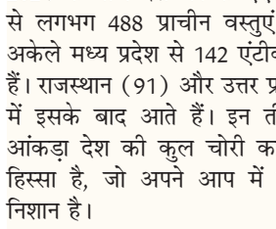


भारतीय हवाई क्षेत्र में चीनी सैन्य विमान ने कर दी घुसपैठ

नई दिल्ली। भारत-चीन सीमा के पास 12 नवंबर को चीनी सैन्य विमान के भारतीय हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने की रिपोर्ट सामने आई है। चीनी विमान सिक्किम क्षेत्र में भारतीय सीमा के भीतर करीब 20 से 25 मिनट तक मंडराता रहा। यह इलाका रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नजदीक है, जिसे 'चिकन नेक' के नाम से भी जाना जाता है। इस घटना ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय वायुसेना ने 12 नवंबर की सुबह करीब 8 बजे चीनी विमान की गतिविधि का पता लगाया। इसके बाद विमान को तत्काल चेतावनी देकर भारतीय क्षेत्र से वापस जाने के लिए कहा गया। हालांकि, चेतावनी के बावजूद विमान कुछ समय तक इलाके में मंडराता रहा। बताया गया है कि विमान करीब 25 हजार फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। रिपोर्ट में चीनी सैन्य विमान के प्रकार, उसके सटीक उड़ान मार्ग और भारतीय क्षेत्र से बाहर निकलने के समय की जानकारी स्पष्ट नहीं की गई है। हालांकि, सिक्किम की रणनीतिक स्थिति और सिलीगुड़ी कॉरिडोर की संवेदनशीलता को देखते हुए इस घटना को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

एमपी के मंदिरों और स्मारकों से गायब हो चुकी हैं 142 बेशकीमती मूर्तियां

भोपाल। मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक स्मारकों और मंदिरों से बेशकीमती धरोहरों के चोरी होने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। हाल ही में शिवपुरी के नरवर फोर्ट से 3.5 टन भारी प्राचीन तोप गायब होने की सनसनीखेज घटना ने सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। आंकड़े बताते हैं कि देश भर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षित स्मारकों से जितनी प्राचीन मूर्तियां और एंटीक चीजें चोरी हुई हैं, उनमें से करीब एक तिहाई यानी 142 अकेले मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखती हैं। आधिकारिक रिकॉर्ड के मुताबिक, साल 1961 से 2024 के बीच देश भर के एएसआई संरक्षित स्थलों से लगभग 488 प्राचीन वस्तुएं चोरी हुई हैं। इनमें अकेले मध्य प्रदेश से 142 एंटीक आइटम गायब हुए हैं। राजस्थान (91) और उत्तर प्रदेश (86) इस सूची में इसके बाद आते हैं। इन तीनों राज्यों का कुल आंकड़ा देश की कुल चोरी का करीब 65 प्रतिशत हिस्सा है, जो अपने आप में एक बड़ा सवालिया निशान है।



स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार का खर्च 3 गुना बढ़ा, परिवारों की जेब से भुगतान घटा

नई दिल्ली। देश में स्वास्थ्य सेवाओं पर होने वाले कुल खर्च में सरकार की हिस्सेदारी बढ़ी है, जबकि कुल खर्च में लोगों को अपनी जेब से इलाज पर खर्च होने वाली हिस्सेदारी पहले के मुकाबले कम ही है। पिछले दस साल में कुल स्वास्थ्य खर्च में लोगों की जेब से सीधे किए जाने वाले भुगतान की हिस्सेदारी 64.2 फीसदी से घटकर 42.7 फीसदी रह गई है। इस दौरान स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार का खर्च तीन गुना से अधिक बढ़कर 4.14 लाख करोड़ रुपये हो गया। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने रविवार को नेशनल हेल्थ अकाउंट्स (एनएचए) 2023-24 की रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के मुताबिक, 2013-14 में देश के कुल स्वास्थ्य खर्च का 64.2 फीसदी हिस्सा लोगों को अपनी जेब से देना पड़ता था। 2023-24 में यह घटकर 42.7 फीसदी रह गया। 2022-23 में लोगों की जेब से होने वाले खर्च की हिस्सेदारी 43.4 फीसदी थी, जो 2023-24 में घटकर 42.7 फीसदी रह गई।

प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं पर 1.53 लाख करोड़ रुपये खर्च

सरकार ने 2023-24 में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं पर करीब 1.53 लाख करोड़ रुपये खर्च किए। इसका मकसद लोगों को घर के नजदीक ही बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इसके तहत आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के जरिये बीमारियों की शुरुआती पहचान, गैर-संचारी रोगों की जांच, जरूरी दवाएं और जांच की सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है।

कुल खर्च का अब भी 42.7 फीसदी लोग अपनी जेब से दे रहे- सरकारी खर्च में बढ़ोतरी के बावजूद इलाज का आर्थिक बोझ पूरी तरह कम नहीं हुआ है। 2023-24 में भी देश के कुल स्वास्थ्य खर्च का 42.7 फीसदी हिस्सा लोगों ने अपनी जेब से चुकाया। यानी स्वास्थ्य सेवाओं पर होने वाले कुल खर्च का बड़ा हिस्सा अब भी आम लोगों को खुद उठाना पड़ रहा है।

नेशनल हेल्थ अकाउंट्स की यह 11वीं रिपोर्ट है। इसे स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत नेशनल हेल्थ सिस्टम्स रिसोर्स सेंटर ने तैयार किया है। रिपोर्ट तैयार करने में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सिस्टम ऑफ हेल्थ अकाउंट्स-2011 के मानकों का इस्तेमाल किया गया है।



सरकारी खर्च 1.30 लाख करोड़ से बढ़कर 4.14 लाख करोड़- स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार का खर्च 2013-14 में 1,29,778 करोड़ रुपये था, जो 2023-24 में बढ़कर 4,14,196 करोड़ रुपये हो गया। यानी दस साल में सरकारी स्वास्थ्य खर्च तीन गुना से अधिक बढ़ा। कुल स्वास्थ्य खर्च में सरकार की हिस्सेदारी भी इस अवधि में 14.9 प्रतिशत अंक बढ़ी है।

हर व्यक्ति पर सरकारी खर्च 1,042 से बढ़कर 2,959 रुपये- प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार के खर्च में भी करीब तीन गुना बढ़ोतरी हुई है। 2013-14 में सरकार प्रति व्यक्ति औसतन 1,042 रुपये खर्च कर रही थी। 2023-24 में यह बढ़कर 2,959 रुपये हो गया। यानी दस साल में प्रति व्यक्ति सरकारी स्वास्थ्य खर्च करीब 2.8 गुना बढ़ा।

भारत में 2015 के बाद से टीबी से होने वाली मौत में 38 फीसदी की कमी आई

भारत ने टीबी के खिलाफ लड़ाई में उपलब्धि हासिल की है। देश में 2015 के बाद से टीबी से होने वाली मौत के मामलों में 38 फीसदी की कमी आई है, जबकि वैश्विक स्तर पर यह गिरावट 35 फीसदी रही। इसके अलावा दवा से ठीक होने वाले टीबी के मरीजों में उपचार की सफलता दर 94 फीसदी रही। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी डब्ल्यूएचओ की 'वैश्विक तपेदिक रिपोर्ट 2026' का हवाला देते हुए कहा कि ये आंकड़े दर्शाते हैं कि भारत टीबी को खत्म करने की दिशा में लगातार प्रगति कर रहा है।

आज मनाया जाएगा जनजातीय गौरव दिवस

सारंगढ़। जनजातीय समाज के गौरवशाली इतिहास, समृद्ध संस्कृति, परंपराओं और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को सम्मान देने के उद्देश्य से जिले में 16 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। जिला स्तरीय कार्यक्रम सुबह 10 बजे शासकीय पंडित लोचन प्रसाद पांडेय महाविद्यालय, सारंगढ़ में आयोजित होगा। कार्यक्रम में रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र के सांसद राधेश्याम राठिया मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे।कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन पुनर्वास तथा उच्च शिक्षा मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री श्री टंकराम वर्मा, वित्त, वाणिज्यिक कर (आबकारी को छोड़कर), आवास एवं पर्यावरण, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री ओ.पी. चौधरी, जांजगीर-चांपा लोकसभा क्षेत्र की सांसद कमलेश जांगड़े, सारंगढ़ विधायक श्रीमती उत्तरी गणपत जांगड़े और बिलाईगढ़ विधायक कविता प्राण लहरे विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। जिला पंचायत अध्यक्ष संजय भूषण पांडेय और नगर पालिका सारंगढ़ अध्यक्ष सोनी अजय बंजारे सहित जनपद पंचायतों एवं नगर पंचायतों के अध्यक्ष, जिला पंचायत और जनपद पंचायत सदस्य तथा जिले के अन्य जनप्रतिनिधि भी कार्यक्रम में शामिल होंगे जनजातीय गौरव दिवस भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर जनजातीय समाज के इतिहास, अस्मिता और देश के स्वतंत्रता आंदोलन में उसके योगदान को स्मरण करने का अवसर है। यह दिन जनजातीय नायकों के संघर्ष, साहस और बलिदान को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के साथ उनकी विशिष्ट सांस्कृतिक विरासत के प्रति सम्मान व्यक्त करने का संदेश देता है।

एनएसएस से मिलता है सेवा और संस्कार का अवसर : डॉ. सिन्हा



सीपत। वैदिक महाविद्यालय सीपत द्वारा ग्राम कारीछापर में आयोजित सात दिवसीय राष्ट्रीय सेवा योजना विशेष शिविर के तीसरे दिन स्वयंसेवकों को नशामुक्त समाज निर्माण और राष्ट्रीय सेवा योजना के महत्व पर महत्वपूर्ण मार्गदर्शन मिला। कार्यक्रम में एनएसएस के कार्यक्रम समन्वयक डॉ. मनोज सिन्हा एवं एनएसएस सहयोगी चन्द्राकर सर विशेष रूप से शामिल हुए। इस दौरान डॉ. मनोज सिन्हा ने स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए कहा कि नशामुक्त समाज का निर्माण केवल एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि पूरे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। युवा शक्ति समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की सबसे बड़ी ताकत है। राष्ट्रीय सेवा योजना युवाओं को समाजसेवा, अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और सामाजिक दायित्वों का बोध कराती है। उन्होंने स्वयंसेवकों को नशे से दूर रहने तथा अपने आसपास के लोगों को भी नशामुक्ति के प्रति जागरूक करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने एनएसएस के उद्देश्य, महत्व एवं गतिविधियों की विस्तार से जानकारी देते हुए स्वयंसेवकों से संवाद किया। साथ ही एनएसएस से संबंधित प्रश्नोत्तरी के माध्यम से विद्यार्थियों के ज्ञान का परीक्षण किया और उनका उत्साहवर्धन किया। प्रश्नोत्तरी में स्वयंसेवकों ने बढ़चढ़कर सहभागिता निभाई। शिविर के दौरान संस्था के रासेयो कार्यक्रम अधिकारी रामेश्वर साहू, सहायक अधिकारी आकांक्षा भारती, सहायक प्राध्यापक जयंत पांडेय सहित बड़ी संख्या में शिविरार्थी उपस्थित रहे

फोटोयुक्त मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों हुई की बैठक



पेण्ड्रा/मरवाही। भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के निर्देशानुसार फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2027 के अंतर्गत अर्हता तिथि 1 जनवरी 2027 के आधार पर तैयार मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन जिले के सभी मतदान केंद्रों एवं निर्धारित स्थानों पर किया गया है। इस संबंध में जिला निर्वाचन कार्यालय में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की जिला स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में भारतीय जनता पार्टी के कुबेर सर्राठी, इंडियन नेशनल कांग्रेस पुष्पराज सिंह ठाकुर, पवन केसरवानी, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी तथा जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। बैठक में विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 24-मरवाही एवं विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 25-कोटा के अंतर्गत मतदान केंद्र क्रमांक 01 से 70 तक की फोटोयुक्त मतदाता सूची की एक-एक मुद्रित प्रति तथा फोटो रहित मतदाता सूची की सॉफ्टकॉपी सीडी के माध्यम से राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराई गई। बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की प्रक्रिया के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही मतदाता सूची में नाम जोड़ने, विलोपन एवं संशोधन से संबंधित प्रपत्र 6, 7 एवं 8 तथा दावा-आपत्ति प्रस्तुत करने की प्रक्रिया से अवगत कराया गया। जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा बताया गया कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का उद्देश्य निर्वाचक नामावली को अद्यतन एवं त्रुटिरहित बनाना है, ताकि सभी पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में दर्ज हो सकें।

ज्ञानोदय विद्यालय में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया बाल दिवस



जांजगीर। ज्ञानोदय विद्यालय जांजगीर में देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के अवसर पर 14 नवंबर को बाल दिवस बड़े ही हर्षोल्लास, उमंग एवं उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालय परिसर में बच्चों के लिए विशेष मनोरंजक गतिविधियों, खेलकूद एवं फन एंड फेयर का आयोजन किया गया। पूरा विद्यालय बच्चों की खिलखिलाहट, मस्ती और खुशियों से सराबोर नजर आया। बाल दिवस के अवसर पर विद्यालय के नन्हे-मुन्ने छात्र-छात्राएं आकर्षक एवं रंग-बिरंगी वेशभूषा में विद्यालय पहुंचे। बच्चों ने चाचा नेहरू, सैनिक, पारंपरिक भारतीय परिधान एवं विभिन्न सांस्कृतिक वेशभूषा धारण कर अपनी मनमोहक छटा बिखेरी। बच्चों का उत्साह और उनकी आकर्षक सजावट कार्यक्रम का विशेष आकर्षण रही। इस दौरान शिक्षिकाओं ने भी बच्चों के साथ उत्साहपूर्वक सहभागिता की और उनका उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों के मनोरंजन के लिए विभिन्न प्रकार के रोचक एवं मनोरंजक गेम्स आयोजित किए गए। इन खेलों में बच्चों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। खेलों के माध्यम से बच्चों को मनोरंजन के साथ-साथ आपसी सहयोग, टीम भावना, अनुशासन एवं स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की सीख भी मिली। बच्चों ने पूरे उत्साह के साथ खेलों में भाग लिया और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया।

पहले दिन जांजगीर-चाम्पा जिले के धान खरीदी केंद्रों में पसरा रहा सन्नाटा

नहीं हो सकी खरीदी की बोहनी, व्यवस्था दुरुस्त करने में जुटे रहे केंद्र प्रभारी

जांजगीर/चांपा। समर्थन मूल्य धान खरीदी का छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से आगाज हो चुका है, वहीं जांजगीर चांपा जिले की बात करें तो बंपर धान उत्पादन के लिए जाना जाने वाला जिला है जहां पर धान खरीदी के पहले उपार्जन केंद्रों में सन्नाटा पसरा रहा। जिले के किसी भी केंद्र में खरीदी की बोहनी भी नहीं हो सका। वहीं केंद्र प्रभारी दिन भर व्यवस्था दुरुस्त करने में लगे रहे।

जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के पहले दिन कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने खोखरा एवं कुटरा धान उपार्जन केंद्रों का निरीक्षण कर खरीदी कार्य एवं किसानों की सुविधा के लिए की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने समिति प्रबंधको से एग्रीस्टैक पंजीयन, धान विक्रय के लिए पंजीकृत किसानों की संख्या तथा टोकन वितरण की स्थिति की जानकारी ली। कलेक्टर ने उपार्जन केंद्रों में जल निकासी की समुचित व्यवस्था रखने, धान की व्यवस्थित स्टैकिंग करने तथा पेयजल, छाया, शेड सहित अन्य मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने धान का सुरक्षित भंडारण सुनिश्चित



करने तथा केंद्रों में निगरानी एवं पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सीसीटीवी कैमरों को सुचारू रूप से संचालित रखने के निर्देश भी दिए। कलेक्टर ने सभी संबंधित अधिकारियों एवं समिति प्रबंधकों को निर्देशित किया कि खरीदी प्रक्रिया के दौरान किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करते हुए समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का कार्य सुचारू, पारदर्शी एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराएं। इस अवसर पर उप पंजीयक सहकारिता श्रीमती मंजू पांडेय, जिला खाद्य अधिकारी श्री संदीप पांडेय ,जिला विपणन अधिकारी श्री मनोज यादव सहित संबंधित अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

सक्ती जिले में 16.80 क्विंटल के साथ हुआ धान खरीदी का शुभारंभ

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी जयश्री जैन और जिला सहकारी उपाध्यक्ष रजनी साहू ने डोडकी धान उपार्जन केन्द्र पहुँचकर धान खरीदी के कार्यों का निरीक्षण किया तथा धान उपार्जन केन्द्र डोडकी में धान विक्रय करने पहुंचे किसान किसान राम कुमार और किसान संतोष कुमार को सम्मानित कर जिले में धान खरीदी कार्य का शुभारंभ किया। धान उपार्जन केंद्र डोडकी में



किसान राम कुमार पिता एसे राम ने आज 10.80 क्विंटल धान विक्रय के लिए पहुंचे। इसी प्रकार डोडकी निवासी किसान संतोष कुमार पिता गोसाईं राम ने आज 6 क्विंटल धान विक्रय करने के लिए पहुंचे। जिस पर कलेक्टर जैन और जिला सहकारी उपाध्यक्ष रजनी साहू की उपस्थिति में किसानो से सुव्यवस्थित रूप से धान खरीदी की गई। इस अवसर पर जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित की उपाध्यक्ष रजनी साहू ने कहा कि आज से धान खरीदी प्रारंभ हो रही है।

गौरेला-पेन्ड्रा-मरवाही जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, 240 बोरी अवैध धान जब्त

खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के अंतर्गत समर्थन मूल्य पर धान खरीदी प्रारंभ होने से पहले जिले में अवैध धान के भंडारण एवं परिवहन पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की जा रही है। कलेक्टर विजय दयाराम के. के मार्गदर्शन में राजस्व, खाद्य एवं मंडी विभाग की संयुक्त टीम ने आज तहसील पेण्ड्रारोड के ग्राम बरवासन में दो अलग-अलग स्थानों पर कार्रवाई करते हुए कुल 240 बोरी अवैध रूप से भंडारित धान जब्त किया।



प्राप्त जानकारी के अनुसार जांच के दौरान ग्राम बरवासन निवासी राजेंद्र गुज्जर की बाड़ी में ट्रैक्टर में रखी 35 बोरी तथा खुले में रखी 100 बोरी सहित कुल 135 बोरी धान पाया गया। इसी प्रकार जीवन सिंह मारको के यहां अवैध रूप से भंडारित 105 बोरी धान पाया गया। संयुक्त जांच दल द्वारा दोनों स्थानों से कुल 240 बोरी धान जब्त कर ग्राम कोटवार की अभिरक्षा में सौंपा गया। जांच के दौरान संबंधित व्यक्तियों से पूछताछ करने पर यह तथ्य सामने आया कि दोनों के खेतों में अभी तक धान की कटाई एवं मिसाई नहीं हुई है। पूछताछ में यह भी जानकारी मिली कि उक्त धान अन्य किसान के खेत से लाकर भंडारित किया गया था।

पुरानी रंजिश को लेकर रास्ते में रोककर की गाली-गलौज, आरोपी से बटनदार चाकू किया बरामद



सीपत। पुरानी रंजिश को लेकर एक बुजुर्ग महिला को रास्ते में रोककर गाली गलौज करने और बटनदार चाकू दिखाकर जान से मारने की धमकी देने के मामले में सीपत पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक स्टील का बटनदार चाकू बरामद कर उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। सीपत पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, ग्राम सेलर निवासी रामकुमारी साहू 60 वर्ष ने 14 नवंबर को सीपत थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि उनके बेटे लक्ष्मीनारायण साहू ने पिछले वर्ष आरोपी दीपक साहू के भाई विशाल साहू की फसल की कटाई हार्वेस्टर से की थी। इसी बात को लेकर दीपक साहू उनके बेटे से रंजिश रखता था। इसी रंजिश के चलते 13 नवंबर को दोपहर करीब 12 बजे जब रामकुमारी साहू गांव के डॉक्टर के पास इलाज कराने पैदल जा रही थीं, तभी आरोपी दीपक साहू ने उन्हें रास्ते में रोक लिया और अश्लील गाली गलौज करने लगा। विरोध करने पर आरोपी ने बटनदार चाकू दिखाते हुए जान से मारने की धमकी दी। मामले की रिपोर्ट पर सीपत पुलिस ने अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की।

बच्चों को शिक्षा के साथ संस्कार भी दें : गुरू खुशवंत साहेब

बम्हनीडीह। ग्राम देवरानी में जय कर्मा जस गीत व्दारा आयोजित श्रीराम कथा के दूसरे दिन सती कथा व पार्वती विवाह का कथावाचक पं प्रेमशंकर चौबे ने श्रद्धालु का मुखारविंद से श्रीराम कथा का अविरल प्रवाह चल रहा है इसी बीच तकनीकी शिक्षा रोजगार मंत्री गुरू खुशवंत साहेब सांसद कमलेश जागड़े पूर्व प्रत्याशी कृष्ण कांत चद्रा सभापति मोहन कुमारी जिला पंचायत अध्यक्ष कीर्तन द्रौपदी चद्रा जनपद पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि गोकुल जायसवाल उपाध्यक्ष प्रतिनिधि दुष्यन्त सिंह राज भाजपा प्रदेश मंत्री सम्पूर्णानंद मिश्रा जिला पंचायत सदस्य उमा राठौर ने कथा स्थल पहुंचकर श्रीराम व भगवान शिव



के पूजा अर्चना कर ब्यास पीठ महराज प्रेमशंकर चौबे से आशीर्वाद प्राप्त किया। तत्पश्चात प्रदेश तकनीकी शिक्षा रोजगार मंत्री गुरू खुशवंत साहेब ने कहा कि आज हर गांव गांव में धार्मिक आयोजन का अविरल धारा बह रही है तथा धार्मिक आयोजन से गांव में शांति खुशहाली और समृद्धि हो रही है इस धार्मिक आयोजन जय कर्मा जसगीत पार्टी का हृदय से आभार व्यक्त किया साथ ही धार्मिक कार्य से बच्चों को शिक्षा और संस्कार वान होने चाहिए तथा सभी आज संकल्प ले कि अपने अपने घर में बच्चों को संस्कार की भावना बच्चों में जाग्रत होनी चाहिए उन्होंने आगे कहा कि आज प्रदेश श्रीराम लला के नैनिहाल भूमि होने के साथ ही प्रदेश में श्रीराम जन्मभूमि अयोध्या के दर्शन के लिए दर्शानार्थियों को दर्शन के लिए भेजा जा रहा है मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ विकास उत्तरोत्तर गति से आगे बढ़ रहा है आप सभी ने जिस विश्वास के साथ भाजपा पार्टी की सरकार बनाया है इससे आम लोग खुश हैं वहीं किसानों के धान खरीदी कर कम रकबा में धान बेचने वाले किसानों को अंतर शेष राशि इनके खाता में डाला जाएगा।वही भाजपा सांसद कमलेश जागड़े ने कहा कि श्रीराम के आदर्शों को जीवन में आत्मसात करके इनके बताएं मार्गो पर चलने की बात कही है वहीं कथा श्रवण करने के बाद महिला बाल विकास सभापति मोहन कुमारी साहू के निज निवास में पहुंच क्षेत्र के समस्या का जानकारी ली तथा हर विकास कार्य को प्राथमिकता से पूरी करने का आश्वासन दिया।

अवैध रूप से धारदार चाकू लहराने वाले दो आरोपी गिरफ्तार

प्रकरण के आरोपी के विरूध्द धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत की गई कार्यवाही, थाना चाम्पा पुलिस की कार्यवाही...



चांपा। मामले में मुकुंद टाकीज चाम्पा का मालिक फोन के माध्यम से सूचना दिया कि दो व्यक्ति धारदार बडा नुकिला चाकू लेकर टाकीज के मोटर सायकल स्टैण्ड के पास खडे है और आने-जाने वाले लोगो को चाकू दिखाकर डरा रहें है कि सूचना पर थाना प्रभारी निरीक्षक कमलेश शेण्डे द्वारा सक्रियता दिखाते हुये तत्काल पेट्रोलिंग पार्टी को भेजकर घटना का तस्दीक कराया जहां दो व्यक्ति को पकडकर पूछताछ किया गया पूछताछ पर अपना नाम उमेश यादव पिता छतराम यादव उम्र 25 वर्ष सा0 खरहरकुडा थाना उरगा जिला कोरबा एवं करन गोस्वामी पिता गोरेलाल गोस्वामी उम्र 24 वर्ष सा0 सा0 नवलपुर थाना उरगा जिला कोरबा का होना बताया गया जिनका पृथक-पृथक तलाशी लेने पर शर्ट के अंदर छिपाये रखे बडा चाकू मिला जिसे जप्त किया गया तथा आरोपीयों का उक्त कृत्य अपराध सदर धारा का पाये जाने से थाना चांपा में अपराध क्रमांक 621/26 धारा 25,27 आर्म्स एक्ट पंजीबद्ध कर आरोपी 01 उमेश यादव पिता छतराम यादव उम्र 25 वर्ष सा0 खरहरकुडा थाना उरगा जिला कोरबा, 02 करन गोस्वामी पिता गोरेलाल गोस्वामी उम्र 24 वर्ष सा0 सा0 नवलपुर थाना उरगा जिला कोरबा (छ0ग0) को दिनांक 14.11.2026 को विधिवत् गिरफ्तार कर आज दिनांक 15.11.2026 को न्यायिक रिमांड हेतु माननीय् न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है।। उक्त कार्यवाही मे थाना प्रभारी चांपा निरीक्षक कमलेश कुमार शेण्डे, उनि भवानी सिंह, प्र0आर0 सुनील सिंह, प्र0आर0 गणेश कौशिक,आर. गौरीशंकर राय, सुमंत कँवर एवं थाना चांपा स्टाफ का सराहनीय योगदान रहा।

जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई गई भगवान बिरसा मुंडा की जयंती

सक्ती। जनजातीय महानायक भगवान बिरसा मुंडा के 151वीं जयंती के मौके पर 15 नवंबर, रविवार को सक्ती विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत सपनईपाली के आश्रित ग्राम चारपारा में स्थित बड़ादेव देवठाना में आदिवासी समाज के लोगों ने बिरसा मुंडा की जयंती उत्साह के साथ मनाया। इस मौके पर कार्यक्रम में चारपारा देवठाना के संस्थापक शिक्षक व चारपारा निवासी घनश्याम सिंह राज - प्रांतीय संयोजक छत्तीसगढ़ गोड़वाना संघ, जवाहर सिंह पोर्ते, जिला प्रचारक गोंडी धर्म संस्कृति संरक्षण समिति छ.ग., धुज राम नेताम प्रथम पुजारी चारपारा देवठाना, पद्मा बाई मरावी, मेमबाई जगत, राजेन बाई पोर्ते, निधि सिदार, विशाल नेताम, महेंद्र सिंह सिदार, कमला देवी जगत, पत्रकार योम प्रकाश लहरे व उदय मधुकर सहित चारपारा देवठाना के



पदाधिकारियों सहित जनजातीय समाज के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। इस मौके पर कार्यक्रम में उपस्थित टेमर ग्राम पटेल रेवती नंदन पटेल व चारपारा ग्राम पटेल मांडवी साहू ने कार्यक्रम में उपस्थित जनजातीय समाज के प्रबुद्धजनों का पीला गमछा भेंटकर सम्मान किया और सबको जनजातीय गौरव दिवस की बधाई दी । इसके पहले कार्यक्रम की शुरुआत भगवान बिरसा मुंडा जी के प्रतिमा पर पूजा अर्चना करने के साथ हुआ। इस मौके पर चारपारा देवठाना के संस्थापक घनश्याम सिंह राज ने भगवान बिरसा मुंडा के जीवन संघर्षों तथा समाज के बेहतरी के लिए उनके द्वारा किए कार्यों के लिए उन्हें नमन किया।

उन्होंने बताया कि जनसाधारण के मन में गोंडी धर्म के प्रचार- प्रसार तथा संस्कृति की रक्षा के लिए चारपारा देवठाना की स्थापना उन्होंने 2009 में पांच दिवसीय बड़ादेव शक्ति स्थापना कार्यक्रम के भव्य आयोजन के साथ हुआ था। जिला प्रचारक गोंडी धर्म संस्कृति संरक्षण समिति के पदाधिकारी जवाहर सिंह पोर्ते ने कहा भगवान बिरसा मुंडा को जनजातीय समाज का गौरव बताते हुए उनकी विचारधारा को आत्मसात कर आगे बढ़ने की अपील किया विदित हो कि बिरसा मुंडा जी का जन्म आज से 150 साल पहले आज ही के दिन 15 नवंबर 1875 को झारखंड राज्य के जिला अंतर्गत ग्राम में हुआ था।

श्री दूधाधारी मठ में हुआ सूर्य पूजन कार्यक्रम



अन्नकूट के पश्चात प्रथम रविवार को किया जाता है सूर्य पूजन

जांजगीर। श्री दूधाधारी मठ में सूर्य पूजन का भव्य कार्यक्रम विधिपूर्वक संपन्न हुआ। परंपरा के अनुसार अन्नकूट के पश्चात प्रथम रविवार को भगवान सूर्य नारायण का विशेष पूजन किया जाता है। कार्यक्रम में श्री दूधाधारी मठ पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर राजेश्री महन्त रामसुन्दर दास जी महाराज ने भगवान सूर्य नारायण का पूजन-अर्चन किया। इस अवसर पर राजेश्री महन्त जी महाराज ने अपने संदेश में कहा कि - पूज्य गुरुदेव जी (राजेश्री महन्त वैष्णव दास) महाराज के द्वारा बताए गए नियम के अनुसार भगवान सूर्य नारायण को 1,108 पुष्प अर्पित किए गए। सूर्यदेव ही समस्त संसार के ऊर्जा के स्रोत हैं।

उनका पूजन करने से मनुष्य को आरोग्य, तेज, बल बुद्धि और सुख-समृद्धि की प्राप्ति होती है। पूजन के पश्चात मठ परिसर में श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद वितरण किया गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालु, संतजन एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे सभी ने सूर्यदेव के दर्शन कर पुण्य लाभ अर्जित किया।

नौकरी के नाम पर 3 लाख की ठगी का आरोप, भाजपा नेत्री पर गिरी गाज

जांजगीर/चांपा। जिले में भाजपा नेत्री और महिला थाना की काउंसलर पूजा राठौर विवादों में घिर गई हैं। नौकरी लगाने के नाम पर 3 लाख रुपये मांगने और रकम लेने के बावजूद नौकरी नहीं दिलाने का आरोप सामने आने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

जांच प्रभावित न हो, इसके लिए पुलिस अधीक्षक ने पूजा राठौर को काउंसलर पद से हटा दिया है। इधर पद से हटाए जाने की कार्रवाई से नाराज पूजा राठौर ने भी मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने दो दिनों के भीतर दोबारा काउंसलर पद पर नियुक्ति नहीं होने पर एसपी कार्यालय के सामने भूख हड़ताल पर बैठने की चेतावनी दी है। नौकरी का झांसा या पैसों का खेल? 3 लाख की डील का आरोप मामले में रायपुर के तेलीबांधा निवासी श्रवण गुप्ता ने वरिष्ठ कार्यालय में शिकायत आवेदन देकर आरोप लगाया है कि पूजा राठौर ने नौकरी लगाने के नाम पर उनसे 3 लाख रुपये की मांग की थी। शिकायत के अनुसार, कुल रकम में से 2 लाख रुपये दिए जा चुके हैं, जबकि 1 लाख रुपये देना बाकी है। आरोप है कि रकम देने के बावजूद न तो नौकरी लगवाई गई और न ही दिए गए पैसे वापस किए गए।



शिकायत सामने आने के बाद मामला पुलिस जांच के दायरे में आ गया है। पद से हटते ही पूजा राठौर ने खोला मोर्चा काउंसलर पद से हटाए जाने की कार्रवाई को पूजा राठौर ने गलत बताया है। उन्होंने पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर अपनी नाराजगी जाहिर की और कहा कि मामले की जांच पूरी होने से पहले ही उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी गई, जो उचित नहीं है। उन्होंने दोबारा काउंसलर पद पर नियुक्त करने की मांग की है। साथ ही दो दिनों का अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि यदि निर्धारित समय में उन्हें फिर से पद पर नियुक्त नहीं किया गया तो वह एसपी कार्यालय के सामने भूख हड़ताल पर बैठेंगी।

डीएसपी ने क्या कहा ?

मामले में डीएसपी एजेंके सतरूपा तारम ने बताया कि रायपुर के तेलीबांधा निवासी प्रार्थी श्रवण गुप्ता ने वरिष्ठ कार्यालय में शिकायत आवेदन दिया है। शिकायत में महिला थाना की काउंसलर पूजा राठौर पर नौकरी लगाने के नाम पर 3 लाख रुपये मांगने का आरोप लगाया गया है। शिकायतकर्ता के अनुसार, रकम में से 1 लाख रुपये देना बाकी है। पैसे देने के बावजूद नौकरी नहीं लगने और रकम वापस नहीं मिलने की शिकायत की गई है।

डीएसपी ने बताया कि शिकायत की जांच की जा रही है। निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए शिकायत मिलते ही काउंसलर को पद से हटाने की कार्रवाई की गई है।

नौकरी के नाम पर पैसे लेने और ठगी के आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही होगी। फिलहाल मामला आरोपों और पुलिस जांच के स्तर पर है।

राज्यपाल डेका ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर किया नमन



रायपुर। राज्यपाल रमेन डेका ने महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और जनजातीय अस्मिता के महानायक भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर उन्हें कोटि-कोटि नमन किया है। लोक भवन में राज्यपाल ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। साथ ही उनकी जयंती के अवसर पर मनाए जाने वाले जनजातीय गौरव दिवस की प्रदेश एवं समस्त देशवासियों को विशेष रूप से सभी जनजातीय भाई-बहनों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव डॉ. सी.आर. प्रसन्ना सहित लोक भवन के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे ।

सुहास देशपांडे बने लोकतंत्र सेनानी संघ के प्रदेश अध्यक्ष



रायपुर। लोकतंत्र सेनानी संघ के प्रदेश अध्यक्ष पद पर वरिष्ठ सेनानी सुहास देशपांडे, रायपुर को नियुक्त किया गया है। उन्होंने दिवाकर तिवारी का स्थान लिया है। यह नियुक्ति लोकतंत्र सेनानी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद कैलाश सोनी द्वारा की गई है। लोकतंत्र सेनानी संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सच्चिदानंद उपासने ने बताया कि लोकतंत्र सेनानी संघ आपातकाल में जेल गए आपातकाल की प्रताड़नाओं के आपातकाल योद्धाओं का राष्ट्रीय संगठन है, जिसकी देश के सभी राज्यों में सक्रिय संगठन इकाइयां कार्यरत हैं। निर्धारित समयावधि में या अन्य कारणों से संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार मनोनयन कर कार्यकारिणी गठन की कार्यवाही संपादित की जाती है। उसी कड़ी में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने छत्तीसगढ़ लोकतंत्र सेनानी संघ के प्रदेश अध्यक्ष पद पर दिवाकर तिवारी के स्थान पर वरिष्ठ सेनानी सुहास देशपांडे को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। उक्त जानकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सच्चिदानंद उपासने को प्रेषित नियुक्ति आदेश में दी है। उपासने ने निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष का आभार व्यक्त करते हुए नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष को शुभकामनाएं दी हैं।

निगम ने बूढ़ातालाब स्वामी विवेकानंद सरोवर में चलाया सफाई अभियान



रायपुर। गंदगी की जनशिकायत मिलते ही नगर निगम जोन 4 स्वास्थ्य विभाग ने बूढ़ातालाब स्वामी विवेकानंद सरोवर की अभियानपूर्वक सफाई करवाई। जोन क्षेत्र अंतर्गत स्वामी विवेकानंद सदर बाजार क्षेत्र में स्थित इस सरोवर में सफाई मित्रों की सहायता से कचरा और गंदगी उठवाकर स्वच्छता कायम की गई। रायपुर नगर पालिक निगम जोन क्रमांक 4 स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा जनहित में जनस्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह सफाई अभियान चलाया गया। टीम ने सरोवर से कचरा और गंदगी उठवाकर जनस्वास्थ्य सुरक्षा बाबत स्वच्छता कायम की। साथ ही समाजहित में पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से जन-जन को स्वच्छता के प्रति जागरूक बनाया गया और गंदगी से संबंधित जनशिकायत का जोन के स्तर पर त्वरित निदान किया गया।

छठ महापर्व की आस्था के साथ प्रकृति की रक्षा भी हमारा धर्म : आदित्य राजे



रायपुर। छठ महापर्व के अवसर पर रायपुर के 13 वर्षीय बाल पर्यावरणविद् आदित्य राजे सिंह ने श्रद्धालुओं से छठी मैया की आराधना के साथ नदियों, जलाशयों एवं छठ घाटों को स्वच्छ रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि छठी मैया को प्रकृति की देवी माना जाता है। सूर्यदेव एवं छठी मैया की उपासना हमें प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी का भी संदेश देती है। श्रद्धालु नदियों में प्लास्टिक, कचरा एवं पूजन सामग्री न डालें तथा घाटों की स्वच्छता बनाए रखने में सहयोग करें। आदित्य राजे ने कहा, सच्ची आस्था तभी सार्थक होगी, जब हम प्रकृति का सम्मान करेंगे। स्वच्छ नदियां और प्रदूषणमुक्त घाट भी हमारी पूजा का हिस्सा होने चाहिए। आदित्य राजे सिंह पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में सक्रिय हैं। उन्हें पर्यावरण विषय में विश्व के सबसे कम उम्र के पीएचडी धारक के रूप में गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में स्थान प्राप्त है। वे पौधारोपण एवं पर्यावरण जागरूकता अभियानों के माध्यम से निरंतर योगदान दे रहे हैं।

चौपाटी में भीषण आग! आधा दर्जन दुकानें जलकर खाक



सिलेंडर ब्लास्ट से मची अफरा-तफरी

रायपुर। राजधानी रायपुर के राजेंद्र नगर स्थित चौपाटी में रविवार दोपहर को लगी भीषण आग में आधा दर्जन दुकानें जलकर खाक हो गईं. आगजनी के बीच सिलेंडर ब्लास्ट होने से एक दुकान को भारी नुकसान पहुंचा है. कुल मिलाकर इस घटना से लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है।

शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका

राजेंद्र नगर स्थित चौपाटी में आग लगने की घटना के पीछे कोई स्पष्ट वजह सामने नहीं आई है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि यह आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है. आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियां के जरिए दमकल कर्मी जुटे हुए हैं। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, चौपाटी में आग लगने की वजह फ्लिहाल स्पष्ट नहीं हो पाई है। हालांकि, आशंका जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग भड़की होगी। देखते ही देखते आग ने आसपास की दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। दुकानों में रखा सामान जलकर पूरी तरह खाक हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की दो गाड़ियों की मदद से लगातार प्रयास किए गए। इस दौरान सिलेंडर ब्लास्ट होने से इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

लाखों के नुकसान का अनुमान

जोन अध्यक्ष सचिन मेघानी ने बताया कि आग लगने की जानकारी मिलते ही पुलिस को सूचना दी गई थी। चौपाटी में खाने-पीने की करीब 5 से 6 दुकानें आग की चपेट में आई हैं। दुकानों में रखा सामान पूरी तरह जल गया है। फिलहाल आग लगने के कारणों और कुल नुकसान का आकलन किया जा रहा है।



कांग्रेस ने आदिवासियों को सिर्फ वोटबैंक समझा भाजपा ने किया असली चिंतनः मुख्यमंत्री

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि इतना हल्का कांग्रेस का वक्तव्य रहता है कि आज आजादी के 79 साल में लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार केंद्र और राज्यों में रही है और कांग्रेस ने हमेशा जनजातीय समाज को वोटबैंक के रूप में इस्तेमाल किया। रायपुर हेलीपैड में पत्रकारों से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री साय ने कहा कि भाजपा की सरकार ने वास्तव में जनजातीय समाज का चिंतन किया है, जनजातीय समाज का समुचित विकास हो, इसके लिए श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जनजातीय कार्य मंत्रालय का गठन किया था। जनजातीय समाज के विकास के लिए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत हुई है, जिसमें छत्तीसगढ़ के 6,691 गाँव शामिल हैं। विशेष रूप से पिछड़ी जनजातियों के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने पीएम जनमन योजना की शुरुआत की है। हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसी पांच जाति हैं और मात्र 3 लाख 20 हजार उनकी आबादी है। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस को चुनौती देते हुए कहा कि कांग्रेस के लोग जाकर उनके बसाहट में जाकर देखें कि जनजातीय समाज के लिए कितना अच्छा कार्य हो रहा है। उनके घर बन रहे हैं, सौर ऊर्जा से बिजली पहुँचाया जा रहा है। जनजातीय समाज के घरों में पानी पहुँच रहा है, राशन कार्ड बन रहा है।

जोरा धान उपार्जन केंद्र में कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने पूजा-अर्चना कर किया धान खरीदी का शुभारंभ



रायपुर। 15 नवंबर से रायपुर जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की शुरुआत हो गई है। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने जोरा स्थित धान उपार्जन केंद्र पहुंचकर विधिवत पूजा-अर्चना की और धान खरीदी का शुभारंभ किया। धान खरीदी को लेकर किसानों में उत्साह देखा जा रहा है। उपार्जन केंद्रों में किसानों की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं।

कलेक्टर डॉ. सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की मंशा के अनुरूप किसानों को धान विक्रय के दौरान बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। जिले के सभी धान खरीदी केंद्रों में मॉइस्चर मशीन, पर्याप्त बारदाना, पेयजल, छाया, बैठने की व्यवस्था सहित सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रत्येक खरीदी केंद्र में निर्धारित समय सुबह 9:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक धान खरीदी की जाएगी। इस दौरान किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। कलेक्टर ने कहा कि धान खरीदी किसानों के लिए महत्वपूर्ण अवसर है। इसे किसानों के साथ त्योहार की तरह मनाते हुए सभी केंद्रों में बेहतर वातावरण और सुविधाजनक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। किसानों को अपनी मेहनत की उपज बेचने के लिए अनावश्यक प्रतीक्षा न करनी पड़े तथा धान की तौल एवं अन्य प्रक्रियाएं सुगमता से पूरी हों।कलेक्टर ने अधिकारियों को अपने दायित्वों का गंभीरतापूर्वक निर्वहन करने तथा खरीदी केंद्रों की व्यवस्थाओं की सतत निगरानी करने के निर्देश दिए।

छग कांग्रेस प्रभारी सुखदेव भगत आज आएंगे छत्तीसगढ़

सरगुजा में खदान प्रभावितों से करेंगे चर्चा



रायपुर। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश प्रभारी और सांसद सुखदेव भगत 16 नवंबर से 3 दिवसीय प्रदेश दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे जशपुर, सरगुजा और बलरामपुर जिले का दौरा करेंगे। उनका खास फोकस सरगुजा संभाग के कोयला खदान प्रभावित इलाकों पर रहेगा। वे प्रभावित ग्रामीणों और संबंधित पक्षों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनेंगे। इसके साथ ही अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों में बूथ स्तरीय जन चौपाल लगाकर कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे।

सुखदेव भगत 16 नवंबर को झारखंड के लोहरदगा से सड़क मार्ग के जरिए छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे। शंख नदी के पास प्रदेश की सीमा पर कांग्रेस कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे। इसके बाद वे जशपुर, बालाछापर, पतराटोली, कांसाबेल और पत्थलगांव में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। पहले दिन का रात्रि विश्राम मैनपाट में प्रस्तावित है। दौरे के दूसरे दिन यानी 17 नवंबर को सुखदेव भगत मैनपाट से उदयपुर पहुंचेंगे। यहां बूथ स्तरीय जन चौपाल में शामिल होने के बाद ग्राम साल्ही जाएंगे। यहां परसा, केते एक्सटेंशन और तारा कोल ब्लॉक से प्रभावित ग्रामीणों और संबंधित हितधारकों के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान कोयला खनन परियोजनाओं से जुड़े मुद्दों, ग्रामीणों की समस्याओं और प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति पर चर्चा होगी। सरगुजा में कोयला खदानों को लेकर लंबे समय से उठ रहे स्थानीय सवालों के बीच इस मुलाकात को अहम माना जा रहा है। इसके बाद वे प्रेमनगर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम कांटारोली (मेंद्रा) में जन चौपाल में शामिल होंगे। शाम को अंबिकापुर पहुंचकर रात्रि विश्राम करेंगे। दौरे के अंतिम दिन 18 नवंबर को सुखदेव भगत अंबिकापुर स्थित राजीव भवन में जिला कांग्रेस कमेटी की संगठनात्मक बैठक लेंगे। इसमें अंबिकापुर, लुंड्रा और सीतापुर विधानसभा क्षेत्रों के संगठनात्मक विषयों पर चर्चा होगी। इसके बाद वे बलरामपुर जिले के राजपुर पहुंचेंगे।

निगम की नोटिस और 25 हजार जुर्माने को ठेकेदार ने दिखाया ठेंगा

सभापति राठौड़ ने दिए वाहन जब्त करने के निर्देश, खुद खड़े होकर करवाई सड़क की धुलाई



रायपुर। रायपुर नगर निगम जोन 2 जोन कमिश्नर की नोटिस पर रेलवे ठेकेदार ने रेलवे स्टेशन गेट नंबर 2 से फाफडीह चौक तक मार्ग में रोड डिवाइडर पर मिट्टी फैलाने के बाद ध्यान ही नहीं दिया। ना तो निगम की नोटिस का जवाब दिया और ना ही जुर्माना की राशि रुपये 25000 नगर निगम जोन 2 को अदा की। जानकारी के अनुसार रायपुर रेलवे स्टेशन परिक्षेत्र में रेलवे विकास हेतु अनुबंधित ठेकेदार द्वारा रायपुर नगर निगम जोन 2 जोन कमिश्नर पी.डी. धृतलहरे द्वारा विगत 7 नवंबर 2026 को जारी लिखित नोटिस और किए गए 25 हजार रुपये जुर्माने की कार्रवाई का कोई असर अब तक संबंधित रेलवे ठेकेदार पर नहीं पड़ा।

रेलवे ठेकेदार ने ना तो नगर निगम जोन 2 जोन कमिश्नर की लिखित नोटिस का कोई जवाब दिया है और ना ही नगर निगम जोन 2 को जुर्माना की राशि अदा की है और ना ही ठेकेदार ने भारी मात्रा में लापरवाहीपूर्वक रेलवे स्टेशन से फाफडीह चौक तक मुख्य सार्वजनिक सड़क मार्ग पर गिराई गई भारी मात्रा में धूल और गंदगी को हटवाया है। रेलवे ठेकेदार की लापरवाही के चलते हो रही अत्यंत जनअसुविधा को देखते हुए रायपुर नगर निगम सभापति सूर्यकान्त राठौड़ ने गहन नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने नगर निगम जोन 2 जोन कमिश्नर को संबंधित रेलवे ठेकेदार पर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई करने और ठेकेदार का वाहन निगम की रोड पर दिखते ही उसे जब्त करने की कार्रवाई करने के कड़े निर्देश दिए। सभापति ने नगर निगम आयुक्त संबित मिश्रा को भी इसमें तत्काल संज्ञान लेकर संबंधित लापरवाह रेलवे ठेकेदार पर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित करवाने के लिए निर्देशित किया है।जनहित में जनसुविधा हेतु सभापति सूर्यकान्त राठौड़ ने स्वयं खड़े होकर मार्ग की धूल हटवाई और उसकी जेटिंग मशीन से सुव्यवस्थित धुलाई करवाई। लापरवाह रेलवे ठेकेदार के चलते नगर निगम रायपुर को जनहितार्थ आकस्मिक राशि व्यय करनी पड़ी।दीपावली पर्व के पूर्व नगर निगम से व्यापक अभियान चलाकर रेलवे स्टेशन गेट नंबर 2 से लेकर नगर निगम जोन 2 क्षेत्र अंतर्गत रमण मंदिर वार्ड क्रमांक 14 के क्षेत्र के अंतर्गत फाफडीह चौक तक की धूल हटवाई गई थी और आज दीप पर्व के बाद सभापति ने स्वयं अपने सामने जेटिंग मशीन को वहां बुलवाकर मार्ग की सुव्यवस्थित धुलाई करवाई।

विश्व मधुमेह दिवस मनाया गया

लक्षणों का इंतजार करना ही सबसे बड़ी गलतीः डॉ. कल्पना दाश



रायपुर। विश्व मधुमेह दिवस 2026-27 की थीम समय रहते कदम उठाएं के साथ एमएमआई नारायणा हॉस्पिटल, रायपुर में विश्व मधुमेह दिवस मनाया गया। इस अवसर पर एंडोक्राइनोलॉजी, डायबिटीज़ एवं मेटाबोलिक मेडिसिन की विजिटिंग कंसल्टेंट डॉ. कल्पना दाश, डीएम (एंडोक्राइनोलॉजी) ने कहा कि डायबिटीज़ के खुद दिखने का इंतजार न करें, उससे पहले कदम उठाएं। डॉ. दाश ने कहा कि ज्यादातर लोग मानते हैं कि डायबिटीज़ होने पर शरीर खुद संकेत देगा, जैसे बहुत प्यास लगना, बार-बार पेशाब आना, बिना वजह वजन घटना। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ आमतौर पर इतने नाटकीय ढंग से शुरू नहीं होती। यह चुपचाप, कई सालों में बढ़ती है और शुरू में कोई साफलक्षण नहीं दिखता। जब तक इसकी पहचान होती है, तब तक कई मरीजों की आँखों, गुर्दों, नसों या दिल पर असर पड़ चुका होता है। डॉ. दाश ने कहा कि अफ्सोस की बात है कि इसी पड़ाव पर कई लोगों को यह कहकर तसल्ली दे दी जाती है कि शुगर थोड़ी ही बढ़ी है। वे बिना किसी साफ योजना के लौट जाते हैं। अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में मैंने बार-बार देखा है कि डायबिटीज़ की रोकथाम का यह सबसे बड़ा छूटा हुआ मौका है। प्री-डायबिटीज़ का मतलब यह नहीं कि डायबिटीज़ होना तय है। यह हस्तक्षेप करने का मौका है।

विचारों से व्यक्ति को बूढ़ा नहीं होना चाहिएः डा. भारतीय

ज्येष्ठ नागरिक मंच सहयोग ने मनाया दिवाली मिलन



रायपुर। उम्र का पड़ाव सिर्फ एक नंबर गेम है...। विचारों से व्यक्ति को कभी बूढ़ा नहीं होना चाहिए। अगर आप विचार से युवा हैं और आपका मन हमेशा सक्रिय रहता है, तो आप बिल्कुल स्वस्थ्य हैं। छोटी-मोटी तकलीफें से घबराने की जरूरत नहीं है। उक्ताशय के विचार आरोग्य धाम मंदिर के एमडी डॉ. विवेक भारतीय ने महाराष्ट्र मंडल में आयोजित ज्येष्ठ नागरिक मंच की संस्था सहयोग के दिवाली मिलन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि कही।

बुजुर्गों को संबोधित करते हुए डॉ. भारतीय ने कहा कि आप सभी उम्र के उस पड़ाव में हैं, जहां खुद की देखभाल करने की आपको जरूरत है। आज लोगों को प्राकृतिक चिकित्सा, एक्यूपंक्चर, योग, ध्यान, डाइट काउंसलिंग बेहद जरूरी है। इस अवसर पर उन्होंने सभी सदस्यों को दीपावली की शुभकामनाएं दीं। 60 62 या 65 साल की उम्र में सेवानिवृत्त होने वाले लोग अपने आपको रिटायर कहते हैं, वास्तव में उन्हें अपने आपको फ्री टायर कहना चाहिए। फ्री टायर का आशय वह व्यक्ति, जो अपने बच्चों, परिजनों, रिश्तेदारों, मित्रों और समाज की मदद करने के लिए हर वक्त फ्री हो यानी उपलब्ध हो। सहयोग के सचिव श्याम सुंदर खंगन और कोषाध्यक्ष दीपक पात्रीकर ने बताया कि कार्यक्रम की शुरुआत गणपति वंदना के साथ की गई।

युवा गायिका प्रकृति दंडवते ने लग जा गले कि फिर हसीं रात हो न हो की सुमधुर प्रस्तुति दी। नवंबर माह में जन्मदिन वाले सुरेश कोड़ापे, सुलभा शेवलीकर, कामिनी पतंगीवार, अर्चना मराठे, विद्या झाड़े, यशवंत श्रीराम कालेले और रंजना काठोटे को शुभकामनाएं देते हुए सम्मानित किया गया।

खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, 300 किलो संदिग्ध पनीर जब्त कर कराया नष्ट

भोपाल से रेलवे के माध्यम से रायपुर पहुंचा था पनीर, पैकिंग पर अंकित थी आगामी तारीख



रायपुर। आम नागरिकों को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिले में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने रेलवे के माध्यम से भोपाल से रायपुर पहुंचे 300 किलोग्राम संदिग्ध पनीर को बाजार में विक्रय होने से पहले ही रोककर नष्ट कराने की कार्रवाई की। नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन दीपक कुमार अग्रवाल (आईएएस) के निर्देशानुसार त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए जिले के खाद्य प्रतिष्ठानों का सघन निरीक्षण किया जा रहा है। साथ ही मिलावटी एवं अमानक खाद्य पदार्थों के निर्माण, विक्रय एवं वितरण में संलग्न प्रतिष्ठानों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

इसी कड़ी में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने रेलवे के माध्यम से भोपाल से रायपुर विक्रय हेतु लाए गए पनीर की जांच की। जांच के दौरान थर्मोकोल के 6 डिब्बों में कुल 300 किलोग्राम पनीर पाया गया। इनमें से 3 डिब्बों में लगभग 150 किलोग्राम 'भोज मीडियम फैट पनीर' पैक था, जिसकी पैकिंग पर 25 नवंबर 2026 की आगामी तारीख अंकित थी। भविष्य की पैकिंग तारीख अंकित होने के कारण पनीर प्रथम दृष्टया संदिग्ध पाया गया। उक्त पनीर भोज फूड्स, भोपाल से बालाजी इंटरप्राइजेस, अग्रोहा कॉलोनी, रायपुर द्वारा विक्रय एवं वितरण के लिए मंगाया गया था। वहीं शेष 3 थर्मोकोल डिब्बों में लगभग 150 किलोग्राम बिना लेबल का पनीर पाया गया। इस पनीर से संबंधित कोई बिल अथवा वाउचर भी उपलब्ध नहीं कराया गया। साथ ही किसी व्यक्ति द्वारा उक्त पनीर पर स्वामित्व का दावा नहीं किया गया, जिससे इसकी गुणवत्ता एवं वैधता संदिग्ध पाई गई। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने दोनों प्रकार के पनीर को प्रथम दृष्टया संदिग्ध पाए जाने पर बाजार में विक्रय एवं वितरण से रोक दिया।

चीन और माइक्रोसॉफ्ट पर निर्भरता घटाने की वैश्विक मुहिम

सनत जैन

दुनिया में आर्थिक और तकनीकी शक्ति का संतुलन तेजी से बदल रहा है। पिछले दो दशकों में सस्ती वस्तुओं, आधुनिक तकनीक और बड़े पैमाने पर किए जा रहे उत्पादन के कारण चीन दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री बन गया है। इसी तरह कंप्यूटर, इंटरनेट, ईमेल, क्लाउड सेवाओं के कारोबारी, सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में माइक्रोसॉफ्ट का वर्चस्व स्थापित हो गया है। पिछले दो वर्षों में जिस तरह के आर्थिक दबाव, आपूर्ति व्यवस्था में बाधाएं, तकनीकी व्यवधान और भू-राजनीतिक तनाव सामने आए हैं. उसने दुनिया के देशों को एक नई चिंता में डाल दिया है। अब सवाल यह है कि क्या कोई भी देश अपनी अर्थव्यवस्था और संचार व्यवस्था को कुछ चुनिंदा देशों और कंपनियों के भरोसे छोड़ सकता है? भारत सहित दुनिया के अनेक देश अब इस निर्भरता से बाहर निकलने के विकल्प तलाश रहे हैं। यह केवल व्यापार के क्षेत्र का ही सवाल नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक स्वतंत्रता और तकनीकी संप्रभुता की चिंता का विषय भी बन चुका है। चीन ने पिछले वर्षों में लिथियम, निकेल, दुर्लभ खनिजों, सौर ऊर्जा उपकरणों, बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, दवा निर्माण के कच्चे माल और सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। दुनिया के अनेक देशों ने सस्ते उत्पादन के कारण चीन से आयात को प्राथमिकता दी। भारत में देवी-देवताओं की मूर्तियों, सजावटी सामान, खिलौनों, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, पटाखों और रोजमर्रा की जरूरत की वस्तुओं में चीनी उत्पादों की पहुंच बढ़ी है। इस निर्भरता का दूसरा पहलू भी सामने आया है। जब चीन किसी महत्वपूर्ण खनिज के निर्यात पर नियंत्रण लगाता है, या व्यापारिक तनाव के बीच आपूर्ति प्रभावित होती है, तो दूसरे देशों के उद्योगों पर सीधा असर पड़ता है। पिछले दो वर्षों में अमेरिका और चीन के बीच तकनीकी प्रतिस्पर्धा, चिप निर्यात पर प्रतिबंध, दुर्लभ खनिजों के निर्यात नियंत्रण और व्यापार शुल्कों ने वैश्विक कंपनियों को अपनी उत्पादन व्यवस्था बदलने के लिए मजबूर किया है। यूरोप भी इलेक्ट्रिक वाहनों, बैटरियों और सौर उपकरणों के मामले में अब चीन पर अत्यधिक निर्भरता कम करने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। इसका परिणाम यह है, अब केवल सस्ता सामान खरीदना पर्याप्त नहीं माना जा रहा। देश यह भी देख रहे हैं कि संकट के समय आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति जारी रहेगी या नहीं। भारत के लिए यह अवसर है, जब वह अपने घरेलू उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन, दवा उद्योग और खनिज प्रसंस्करण क्षमता को मजबूत करे। इसी तरह से वैश्विक स्तर पर तकनीकी और इंटरनेट के क्षेत्र में माइक्रोसॉफ्ट की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। पिछले कुछ वर्षों से इसके दुष्प्रभाव विभिन्न सेवाओं के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर देखने को मिल रहे हैं। ऐसी स्थिति में कई देश अब अपनी खुद की तकनीकी और इंटरनेट की सेवाएं किस तरीके से हों जिसमें माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर कम आश्रित रहना पड़े, इस दिशा में काम शुरू कर चुके हैं। कई देश अपने सॉफ्टवेयर की शुरुआत कर चुके हैं, इनमें फ्रांस, जर्मनी, ऑस्टिया समेत भारत भी है। फ्रांस में तो साल 2027 तक सरकारी विभाग व जूम नहीं अपना वीडियो-कॉल प्लेटफॉर्म विजियो अपनाएंगे। भारत भी सरकारी ईमेल जोहो क्लाउड का इस्तेमाल कर रहा है। इस प्रकार भारत समेत दुनिया के कई देश अब तकनिकी और सेवाओं के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसमें उन्हें कितनी सफलता मिलेगी यह कहना मुश्किल है, लेकिन इतना तय है कि आने वाले समय में माइक्रोसॉफ्ट के लिए भी दुनिया भर में चुनौती बढने जा रही है। इसके आसार अभी से देखने लगे हैं।

भारत ही विभिन्न देशों में शांति स्थापित कर सकता है

प्रहलाद सबनानी



आज वैश्विक स्तर पर विभिन्न देशों के बीच कई युद्ध चल रहे हैं एवं कई देशों के बीच आपस में तनाव चरम पर पहुंच गया है तथा हो सकता है कि कुछ समय पश्चात इन देशों के बीच भी युद्ध छिड़ जाए। रूस-यूक्रेन युद्ध तो पिछले लगभग 4 वर्ष से अधिक समय से चल ही रहा है। इजराईल-फिलिस्तीन युद्ध भी लम्बे समय से चल रहा है। अमेरिका-ईरान युद्ध को भी 6 माह से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है एवं इस युद्ध ने तो खाड़ी के कई देशों को भी अपनी चपेट में ले लिया है एवं सऊदी अरब एवं ईरान समर्थित हूथी विद्रोहियों के बीच भी युद्ध छिड़ चुका है। अजरबैजान-आर्मेनिया के बीच, चीन-ताइवान के बीच, उत्तर कोरिया-दक्षिण कोरिया के बीच एवं भारत-चीन के बीच भी लगातार तनाव बना ही रहता है। विभिन्न देशों की सरकारों के बीच दरअसल अहं का भाव चरम पर पहुंच गया है, इसके चलते वे आपस में समझौता करने को बिलकुल तैयार नहीं हैं। अब प्रश्न यह किया जा रहा है कि ऐसे कठिन समय में विभिन्न देशों के बीच शांति स्थापित करने के उद्देश्य से भारत के माध्यम से विश्व बंधुत्व के भाव को जगाने हेतु क्या हिंदू सनातन संस्कृति को अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी नहीं चाहिए ?

विश्व बंधुत्व के भाव में विश्व के समस्त देशों के बीच आपस में भाईचारा और प्रेम की भावना स्थापित करना शामिल है। बंधुत्व का भाव जगाने के बाद विभिन्न देशों के समस्त नागरिक भी आपस में बिना किसी भेदभाव के मिलजुलकर मित्रवत भाव के साथ रहने की ओर आगे बढ़ेंगे। सच्चा मित्र उसे कहते हैं जो किसी भी संकट, उत्सव अथवा देश पर आपदा आने पर एक दूसरे की सहायता करता है। साथ ही, मित्र आपस में द्वेष, बैर और हिंसा की भावना का त्याग करते हैं। हिंदू सनातन संस्कारों के अनुसार, भारत में तो यह विश्वास किया जाता है कि समस्त प्राणियों में ईश्वर का वास है, अत: पूरे विश्व के नागरिक आपस में सहोदर हैं। इसी दृष्टि से, भारतीय वसुधैव कुटुम्बकम की भावना में विश्वास रखते हैं, अर्थात विश्व के समस्त नागरिक आपस में भाई बंधु हैं एवं एक ही परिवार के सदस्य हैं।

11 सितम्बर 1893 को दिए गए स्वामी विवेकानंद जी के विश्व विख्यात शिकागो व्याख्यान को 133 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। स्वामी जी ने उक्त धर्म सभा में भारत के सर्वसमावेशी एकात्म और सर्वांगीण जीवन दृष्टि के आधार पर विश्वबंधुत्व का विचार सबके सम्मुख रखा था। उन्होंने अपने हृदय के भाव प्रकट किये थे। स्वामी जी ने अपने इस ऐतिहासिक संबोधन की शुरुआत ही 'मेरे अमेरिकन बहनों और भाईयो' कहकर की थी, जिसे सुन कर पूर्ण सभागार अचंभित और उत्तेजित हो उठा था और कई मिनटों तक खड़े होकर लगातार तालियां बजाकर स्वामी जी का अभिवादन किया था। अपने उदबोधन में स्वामी जी ने कहा था कि- मैं एक ऐसे धर्म का अनुयायी होने में गर्व का अनुभव करता हूं, जिसने संसार को सहिष्णुता तथा सार्वभौम स्वीकृति, दोनों की ही शिक्षा दी है। हम लोग सब धर्मों के प्रति केवल सहिष्णुता में ही विश्वास नहीं करते, वरन् समस्त धर्मों को सच्चा मान कर स्वीकार करते हैं। मुझे ऐसे देश का व्यक्ति होने का अभिमान है, जिसने इस पृथ्वी के समस्त धर्मों और देशों के उत्पीड़ितों और शरणार्थियों को आश्रय दिया है। मुझे आपको यह बतलाते हुए गर्व होता है कि हमने अपने वक्ष में यहूदियों को स्थान दिया था, जिन्होंने दक्षिण भारत आकर उसी वर्ष शरण ली थी, जिस वर्ष उनका पवित्र मन्दिर रोमन जाति के अत्याचार से धूल में मिला दिया गया था। स्वामी जी अपने उदबोधन में आगे कहते हैं कि साम्प्रदायिकता, हठधर्मिता और उनकी वीभत्स वंशधर धर्मान्धता इस सुन्दर पृथ्वी पर बहुत समय तक राज्य कर चुकी है। वह पृथ्वी को हिंसा से भरती रही है, उसको बारम्बार मानवों के रक्त से नहलाती रही है, सभ्यताओं का विध्वंस करती और पूरे पूरे देशों को निराशा के गर्त में डालती रही है। यदि यह वीभत्स दानवता न होती, तो मानव समाज आज की अवस्था से कहीं अधिक उन्नत हो गया होता।

स्वामी विवेकानंद की एकता की परिकल्पना केवल धार्मिक एकता तक सीमित नहीं थी। उनके लिए एकता का अर्थ था - मनुष्य और मनुष्य के बीच एकता, समाज और समाज के बीच एकता, धर्मों के बीच समन्वय तथा समस्त मानवता में एक ही चेतना का दर्शन। भारतीय संस्कृति में हजारों वर्षों से यह विचार रहा है कि सम्पूर्ण विश्व एक परिवार है।

अयं निज: परो वेति गणना लघुचेतसाम्।
उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्॥

अर्थात, संकीर्ण दृष्टि वाले लोग अपना और पराया देखते हैं, जबकि उदार चरित्र वाले सम्पूर्ण पृथ्वी को अपना परिवार मानते हैं। स्वामी विवेकानंद जी की दृष्टि में विश्व की समस्याओं का समाधान विभाजन और संघर्ष में नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर निहित एकत्व की अनुभूति में था।

स्वामी विवेकानंद जी के उक्त विचारों को भारत ने जिया है। लगभग इन्हीं विचारों को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूज्य सर संघचालक माननीय डा मोहन भागवत जी विजया दशमी 2026 के अपने उदबोधन में कहते हैं कि भारत जैसे, मत, पंथ, सम्प्रदाय, प्रांत, जाति, भाषा, खानपान, रीतिरिवाज, आदि विविधताओं से भरपूर, देश में जो विचार इन सभी को स्वीकार करता है, सम्मान देता हैं, अपनेपन से देखता है, वही हमारी एकता का आधार बन सकता है। सौभाग्य से भारत में सनातन काल से चलती आई परम्परा, जो अनेक आध्यात्मिक महापुरुषों की प्रत्यक्ष अनुभूतियों से निरंतर स्पष्ट व पुष्ट होती आयी है, वह हमें बताती है कि सृष्टि की विविधता जितनी स्वाभाविक परंतु परिवर्तनशील है उतनी ही सम्पूर्ण अस्तित्व की एकता शाश्वत, अटल व अचल सत्य है। मनुष्य विचारशील प्राणी होने के नाते उस एकता को स्वयं में तथा जगत में अनुभव कर सकता है। यह करने से ही शाश्वत व नित्य सुख के खोज की जीवमात्र की यात्रा सफल व पूर्ण होती है। सभी विविधताओं को सम्मान देते हुए एवं स्वीकार करते हुए उनको संरक्षण देने का भारत का स्वभाव तथा जो परिवर्तनीय एवं/अथवा कालविसंगत है उसे बदलते रहने का लचीलापन इसी सनातन दृष्टि का परिणाम है। जब जब भारत के जनों में यह भाव सर्वोच्च रहा तब तब भारत विश्व का सभी दृष्टि से आदर्श राष्ट्र रहा। जब आत्मविस्मृति, विघटन व परस्पर सम्पर्क टूटने के कारण हम बलहीन, संकुचित, अहंकारी अथवा भयग्रस्त हो गए, हमने इस आचरण को त्याग दिया, तब हमारी दुर्गति हुई।

डा. भागवत जी आगे कहते हैं कि विश्व में भारत के प्रति एक कुतूहल जाग रहा है। जड़वाद, व्यक्तिवाद तथा संयम रहित उपभोग पर आधारित अधूरी दृष्टि के कारण भौतिक दृष्टि से सम्पन्न होते हुए भी वे देश चिंता में हैं। विविधताओं को कैसे सम्भालना, विकास व पर्यावरण को कैसे साथ चलाना, जो अपने जैसे नहीं हैं उनसे अपनेपन से कैसे बरतना, कुटुंबजीवन के तथा नई पीढ़ियों में संस्कारों के क्षरण को कैसे रोकना आदि समस्याओं का उत्तर उनके पास नहीं है। इसीलिए विश्व आज भूराजनैतिक तनावों के, आर्थिक अनिश्चितता के, पर्यावरणीय संकट के और वर्चस्व की लड़ाई में विनाश को देख रहा है। भारत के पास इन सब समस्याओं के सारे उत्तर हैं, यह वे जानते हैं।

अब यह कहा जा सकता है कि हिंदू भाव व हिंदू स्वभाव ही हमारी एकता का आधार है। कोई विशिष्ट पूजा पद्धति, कोई विशिष्ट खान पान, रहन सहन, कोई सामाजिक या राजनीतिक मतवाद किसी विशिष्ट जाति, भाषा, प्रांत इस की अनिवार्यता इसमें नहीं है। इन सब से ऊपर आध्यात्मिकता, मानवता तथा विश्वबंधुत्व ही इसके लक्षण हैं। भारतीयों में इस भाव के विद्यमान होने से ही भा याने ज्ञान के प्रकाश में रत भारत यह भारतीयतता की एक परिभाषा बनी है। पूरे विश्व को जोड़ सकने वाले व जोड़ना चाहने वाले इस हिंदू भाव का स्मरण व पोषण भारत की प्रगति व एकता की अनिवार्य आवश्यकता है। भारत में इस भाव का रूप उत्कट भारत भक्ति, हम सभी भारतीयों में अपनी समान पूर्वज परम्परा का गौरव एवं आदर्श तथा भारत की सनातन संस्कृति के मूल्यबोध के अनुरूप स्वयं के जीवन को गढ़ते जाना है। प्राचीन काल से भारत भूमि पर निवास करने वाला जनसमूह इसी दृष्टि को लेकर एक समाज के नाते जीता आया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसी हिंदू भाव को जगाकर सम्पूर्ण समाज को एक सुसंगठित व बलसम्पन्न समाज बनाने के लिए कार्य कर रहा है। व्यक्तिजीवन से विश्वजीवन तक की धारणा, प्रतिष्ठा तथा सुरक्षा भी बिना सामर्थ्य के सम्भव नहीं। अतएव संगठित व बलसंपन्न हिंदूसमाज की बात करना या उसके लिए कार्य करना सर्व पंथ समादर की भावना अथवा राष्ट्र की भावनिक एकात्मकता के विरुद्ध नहीं है; हिंदू समाज का विचार व स्वभाव समावेशक होने के नाते ऐसा कार्य हम सब की भावनिक एकात्मता, सद्भावना व सदाचार का पोशक ही होगा यह बात समझनी चाहिए। कुल मिलाकर, आज की वैश्विक परिस्थितियों के बीच भारत द्वारा विभिन्न देशों के बीच विश्व बंधुत्व के भाव को जगाकर, भविष्य में होने वाले तीसरे विश्व युद्ध को रोका जा सकता है।

भारतीय दार्शनिक सम्प्रदाय



24- दिङ्नाग सम्प्रदाय का न्यायवाद

गतांक से आगे...

परन्तु कुछ बस्तु केवल हमारी कल्पना में होती हैं जिनका बाह्य जगत् में होना प्रतीत भी नहीं होता, उनका अस्तित्व केवल परिकल्पित माना गया है। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि शङ्कर के अद्वैतवाद में जो तीन प्रकार की, पारमार्थिक, व्यावहारिक और प्रातिभासिक, सत्ता मानी जाती हैं उनका प्रारम्भ शून्यवाद और योगाचार से ही हुआ था।

24- दिङ्नाग सम्प्रदाय का न्यायवाद

5वीं सदी में किसी समय भारतीय दर्शन के आकारा में एक जाज्वल्यमान तारे के रूप में दिङ्नाग का उदय हुआ। बौद्ध जनश्रुति के अनुसार दिङ्नाग बसुबन्धु के शिष्य थे।

उत्तरकालीन सारे भारतीय दर्शन पर विशेषकर न्यायवैशेषिक और पूर्वमीमांसा के बाह्यार्थवाद (realism) पर उसकी अमिट छाप है। यह कहा जा चुका है कि जिस प्रकार वेदान्त के अद्वैतवाद को नागार्जुन से स्फूर्त्ति और प्रेरणा मिली, उसी प्रकार भारतीय बाह्यार्थवाद (realism) को दिङ्नाग से। परन्तु दोनों में अन्तर यह है की अद्वैतवाद ने थोड़ा सा उलट पलट कर नागार्जुन की विचारपद्धति को स्वीकार किया, परन्तु इधर दिङ्नाग ने न्याय-वैशेषिक के रूढ वाह्यार्थवाद (Naive Realism) पर जो आक्रमण किया, उसके उत्तर और प्रत्युत्तर रूप लगभग 500 वर्षों के लगातार संघर्ष में ही भारतीय बाह्यार्थवाद (Indian Realism) की रूपरेखा तय्यार हुई। दिङ्नाग ने विशेषकर न्याय के वात्स्यायन भाष्य पर आक्रमण किया था, जिसका उत्तर उद्योतकर ने न्यायवार्त्तिक में दिया। इसी बौद्ध-न्याय-संघर्ष ने भारत के कतिपय सबसे महान् दार्शनिक जैसे उद्योतकर, धर्मकीर्त्ति, कुमारिल, प्रभाकर, धर्मोत्तर, वाचस्पति मिश्र, जयन्त, श्रीधर और उद्यन आदि को जन्म दिया।

क्रमश: ...

राष्ट्रीय प्रेस दिवस और इसकी प्रासंगिकता

सुनील कुमार महला



16 नवंबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। वास्तव में यह दिन केवल पत्रकारिता के महत्व को याद करने का अवसर नहीं है, बल्कि यह मीडिया की स्वतंत्रता, निष्पक्षता, विश्वसनीयता और सामाजिक जिम्मेदारी पर आत्ममंथन करने का भी अवसर है। बहरहाल , यहां पाठकों को बताता चलूं कि भारतीय प्रेस परिषद ने आज ही के दिन यानी कि 16 नवंबर, 1966 को कार्य करना प्रारंभ किया था और इसी ऐतिहासिक दिन की स्मृति में राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है।

जैसा कि हम सभी यह जानते हैं कि लोकतंत्र में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के साथ मीडिया की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।शायद यही कारण है कि मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, क्योंकि यह जनता और शासन के बीच संवाद का माध्यम बनता है। सत्ता के निर्णयों को जनता तक पहुँचाना, जनसमस्याओं को शासन के सामने रखना, व्यवस्थागत कमियों को उजागर करना और नागरिकों को उनके अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना पत्रकारिता के प्रमुख दायित्व हैं।

उल्लेखनीय है कि समय के साथ ही साथ आज सूचना और तकनीक के क्षेत्र में अभूतपूर्व बदलाव आया है। समाचार पत्रों और टेलीविजन के साथ डिजिटल मीडिया, समाचार पोर्टल और सोशल मीडिया ने सूचना के प्रसार को अत्यंत तीव्र बना दिया है। अब कोई भी घटना कुछ ही क्षणों में दुनिया के कोने-कोने तक पहुँच जाती है। यह बदलाव जहाँ सूचना की पहुँच को व्यापक बना रहा है, वहीं कई नई चुनौतियाँ भी खड़ी कर रहा है। अधूरी जानकारी, भ्रामक खबरें, फर्जी समाचार, भ्रामक शीर्षक और बिना पुष्टि के प्रसारित सामग्री समाज में भ्रम, अविश्वास और तनाव पैदा कर सकती है। ऐसे समय में पत्रकारिता की विश्वसनीयता और उसकी जिम्मेदारी पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है।

पत्रकारिता का उद्देश्य केवल खबरों को सबसे पहले प्रसारित करना नहीं, बल्कि सही तथ्यों के साथ उन्हें समाज के सामने रखना भी है। कुत्ता आदमी को काट ले,यह खबर नहीं है। आदमी कुत्ते को काट ले, खबर वह है, क्यों कि जो अप्रत्याशित है,वहीं ख़बर है। वास्तव में,ख़बर की पुष्टि, स्रोतों की विश्वसनीयता, दोनों पक्षों को सुनना और भाषा की मर्यादा बनाए रखना निष्पक्ष पत्रकारिता की बुनियादी शर्तें हैं। किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा, सामाजिक सौहार्द और राष्ट्रीय एकता को प्रभावित करने वाली खबरों में विशेष सावधानी अपेक्षित है। सनसनीखेज प्रस्तुति और टीआरपी की होड़ में समाचार की मूल आत्मा प्रभावित नहीं होनी चाहिए, जैसा कि आज हो रहा है। इतना ही नहीं, आज पत्रकारिता के सामने एक बड़ी चुनौती आर्थिक दबाव, व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा और विभिन्न प्रकार के प्रभावों के बीच अपनी संपादकीय स्वतंत्रता बनाए रखने की भी है। पत्रकारिता तभी सार्थक हो सकती है, जब वह किसी पक्ष विशेष के हितों के बजाय जनहित को प्राथमिकता दे। सरकार की उपलब्धियों को सामने लाना जितना आवश्यक है, उतना ही आवश्यक उसकी कमियों और जनसमस्याओं पर सवाल उठाना भी है।

मोदी से लड़ने के लिए राहुल गांधी ने उतारी विदेशी फौज!

नीरज कुमार दुबे



क्या राहुल गांधी को अपनी पार्टी के नेताओं और विपक्षी गठबंधन ढ्ढह्लष्ठढ्ढ के सहयोगियों पर इतना भी भरोसा नहीं रह गया है कि वे उनके साथ मिलकर नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ राजनीतिक लड़ाई लड़ सकें? क्या कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों में ऐसे नेताओं की कमी हो गई है जो भारतीय मतदाताओं के बीच अपनी बात रख सकें और चुनावी राजनीति में कोई सकारात्मक नतीजा हासिल कर सकें? आखिर राहुल गांधी को इसके लिए विदेशी राजनीतिक हस्तियों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों से जुड़े चेहरों का सहारा क्यों लेना पड़ रहा है? देखा जाये तो अब तक राहुल गांधी पर विदेशी ताकतों के इशारे पर भारत की राजनीति करने के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन हैदराबाद के %भारत समिट 2026% में तो तस्वीर इससे भी आगे जाती दिखाई दी। यहां विदेशी मेहमानों को बुलाकर उनसे भारत की चुनी हुई सरकार के खिलाफ बयान दिलवाए गए, भारतीय लोकतंत्र पर सवाल उठवाए गए और राहुल गांधी खुद मंच पर बैठकर इन टिप्पणियों पर तालियां बजाते नजर आए। क्या यह भारत की राजनीति में विदेशी हस्तक्षेप को आमंत्रित करने जैसा नहीं है? क्या अब नरेंद्र मोदी सरकार का राजनीतिक विरोध करने के लिए कांग्रेस को विदेशी ताकतों के कंधों की जरूरत पड़ने लगी है?

हम आपको बता दें कि सबसे दिलचस्प नाम इटली के जियाकोमो फिलिबेक का है। फिलिबेक ने सम्मेलन में राहुल गांधी के समर्थन में न केवल भारतीय लोकतंत्र को निशाना बनाया, बल्कि खुले मंच से नारा लगा दिया- %वोट चोर, गद्दी छोड़!% उन्होंने भारत में लोकतंत्र पर हमला होने का दावा करते हुए अंतरराष्ट्रीय समुदाय से राहुल गांधी और कांग्रेस के साथ खड़े होने की अपील भी की। और सामने बैठे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मुस्कुराते हुए तालियां बजाते रहे। सवाल है कि क्या भारत की राजनीति में विदेशी नेताओं को इस तरह हस्तक्षेप करने का खुला मंच देना कांग्रेस की नई राजनीतिक रणनीति है?

हम आपको बता दें कि फिलिबेक का अतीत भी कम दिलचस्प नहीं है। अप्रैल 2018 में फिलीपींस के अधिकारियों ने उन्हें मनीला में प्रवेश देने से इनकार कर दिया था और वापस भेज दिया था। फिलीपींस के आव्रजन विभाग के मुताबिक, उन्होंने पहले पर्यटक वीजा पर रहते हुए राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेकर अपने प्रवास की शर्तों का उल्लंघन किया था। देखा जाये तो यहां सवाल उठता है कि जिस व्यक्ति के मामले में दूसरे देश ने अपने आंतरिक राजनीतिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप का सवाल उठाया, उसी व्यक्ति को कांग्रेस भारत में अपने राजनीतिक मंच पर जगह क्यों दे रही है। क्या कांग्रेस को इस विरोधाभास का एहसास नहीं था?

साथ ही मामला केवल फिलिबेक तक सीमित नहीं है। सम्मेलन में इक्वाडोर के पूर्व विदेश मंत्री गुइलाउम लॉन्ग, ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के पूर्व अध्यक्ष पैट्रिक गैस्पर्ड और एमनेस्टी इंटरनेशनल के पूर्व महासचिव सलील शेट्टी जैसे नामों की मौजूदगी और निमंत्रण को लेकर भी भाजपा ने गंभीर सवाल उठाए हैं। भाजपा का आरोप है कि सम्मेलन से जुड़े कुछ लोगों के संबंध जॉर्ज सोरोस समर्थित संस्थाओं और नेटवर्क से रहे हैं।

हम आपको बता दें कि गुइलाउम लॉन्ग जिस सेंटर फॉर इकोनॉमिक पॉलिसी रिसर्च (ष्टश्वक्क) से जुड़े हैं, उसे 2021 में सोरोस समर्थित ओपन सोसाइटी पॉलिसी सेंटर से 4.20 लाख डॉलर का अनुदान मिलने की बात भाजपा ने उठाई है। वहीं सलील शेट्टी को लेकर भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कश्मीर पर 2019 में दिए गए उनके बयानों का मुद्दा उठाया है।

अब सवाल यह है कि कांग्रेस ने इन तमाम अंतरराष्ट्रीय हस्तियों को एक साथ भारत में आमंत्रित करने के पीछे कौन-सा उद्देश्य रखा था? क्या यह महज विचार-विमर्श था या भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक विशेष राजनीतिक नैरेटिव तैयार करने की कोशिश थी?

हम आपको यह भी बता दें कि राहुल गांधी ने इसी सम्मेलन में कहा कि भारत अब लोकतंत्र नहीं रह गया है। उन्होंने मोदी सरकार को सत्ता से हटाने का भरोसा जताया और विदेशी मेहमानों के सामने भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, चुनाव और संस्थाओं पर गंभीर आरोप लगाए। देखा जाये तो जब देश का नेता प्रतिपक्ष ही कभी विदेशी धरती से और कभी देसी धरती पर विदेशी प्रतिनिधियों को बुलाकर उनके सामने अपने देश के लोकतंत्र को कठघरे में खड़ा कर रहा हो, तब सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर वह दुनिया को क्या संदेश देना चाहता है?

उधर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसी मुद्दे पर राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए कहा कि भारत को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर बदनाम करके सत्ता हासिल नहीं की जा सकती। शाह ने तंज कसते हुए कहा कि अगर राहुल गांधी को सत्ता में लौटना है तो विदेश यात्राएं छोड़कर गांवों में जाना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस पर लगातार चुनावी हार की हताशा अंतरराष्ट्रीय मंचों पर निकालने का आरोप भी लगाया।

हम आपको यह भी बता दें कि भाजपा नेताओं के हमले के बाद कांग्रेस को सफाई देनी पड़ रही है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने भाजपा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा कि अगर कोई विदेशी आकर ऐसा नारा लगाता है तो आत्ममंथन की जरूरत है।

राजनीतिक तौर पर देखें तो कांग्रेस ने इस सम्मेलन के जरिए भाजपा को एक बड़ा मुद्दा थमा दिया है। अब चुनावी बहस केवल वोट चोरी के आरोपों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि विदेशी राजनीतिक हस्तियों की भूमिका, उनके संस्थागत संबंधों और राहुल गांधी की राजनीतिक स्वीकार्यता पर भी सवाल उठेंगे।

सवाल यह भी उठता है कि आखिर भारत का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, इसका फैसला भारत के मतदाता करेंगे या विदेशी राजनीतिक संगठनों के प्रतिनिधि? क्या कांग्रेस को लगता है कि विदेशी नेताओं से अपने राजनीतिक नारों की पुष्टि करवाकर वह भारतीय जनता के बीच अपनी विश्वसनीयता बढ़ा लेगी? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब विदेशी मेहमान भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाएं, तब क्या लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी अपने देश की संस्थाओं का पक्ष रखने की भी नहीं है?

बहरहाल, हैदराबाद का यह सम्मेलन कांग्रेस के लिए राजनीतिक उपलब्धि से ज्यादा राजनीतिक जवाबदेही का विषय बनता दिखाई दे रहा है। अब राहुल गांधी को बताना होगा कि भारत समिट में भारत की बात हुई थी या भारत की छवि को अंतरराष्ट्रीय मंच पर कठघरे में खड़ा करने की राजनीति हुई थी?

आज का इतिहास

1810 निगवेल हिदाल्गो ने स्पेन से मैक्सिको की आजादी के लिए संघर्ष शुरू किया।
1821 मैक्सिको की स्वतंत्रता को मान्यता मिली।
1849 विश्व प्रसिद्ध रूसी लेखक फ्योदोर दोस्तोविस्की को एक भूमिगत संगठन का सदस्य होने के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई थी।
1870 ओकलाहोमा अमेरिका का 46वां प्रांत बना।
1914 अमरीका में फेडरल रिजर्व व्यवस्था का औपचारिक रूप से शुभारंभ हुआ।
1938 अल्बर्ट होफमैन का आविष्कार लाइर्सेजिक एसिड डाइथलामाइड ड्रग आज ही के दिन वजूद में आया।
1942 अभी दूसरा विश्व युद्ध ख़त्म भी नहीं हुआ था, जब कुछ यूरोपीय देशों की सरकारों ने 1945 में ब्रिटेन में एक सम्मेलन आयोजित किया।
1947 टोक्यो के सईतामा में चक्रवाती तूफान कैथलीन से 1,930 लोगों की मौत हो गई।
1965 वॉल्ट डिज्नी वर्ल्ड के बारे में पहली सार्वजनिक घोषणा हुई।
1973 स्काईलैब-4 को पृथ्वी की कक्षा में प्रक्षेपित किया गया।
1975 केप वर्डे, मोजाम्बिक, साओ टोमे और प्रिंसिप संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुए। पापुआ न्यू गिनी ने ऑस्ट्रेलिया से स्वतंत्रता हासिल की।
1995 भारतीय मूल के वासुदेव पाण्डे त्रिनिदाद एवं टौबेगो के प्रधानमंत्री बने।
1997 चीन के लोकतंत्र समर्थक नेता जिंग शेंग 18 वर्ष बाद रिहा किये गए।
1998 कनाडा ने अपना यहाँ नागरिकता क़ानून को सख्त बनाया।
2000 रूस द्वारा अंतरिक्ष केन्द्र मीर को डुबाने का फैसला।
2001 अफ़ग़ानिस्तान हेतु संयुक्त राष्ट्र के 21 सदस्यीय दल में भारत शामिल।
2002 मुशर्रफ़ ने पांच साल के दूसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति पद की शपथ ली।
2006 पाकिस्तान ने मध्यम दूरी के गौरी-ङ्क मिसाइल का सफल परीक्षण किया।
2007 बंगाल की खाड़ी से उठे भीषण चक्रवाती तूफ़ान %सीडर% ने बांग्ला देश में भीषण तबाही मचाई। वन टू गो एयरलांइस का विमान थाईलैंड में दुर्घटनाग्रस्त होने से 89 लोगों की मौत।
2008 स्टेट बैंक की हेवरा के 58 लाख रुपये की कर्ज़ माफ़ की। चन्द्रयान के लूनर लेजर रेजिंग उपकरण ने सफलतापूर्वक काम करना शुरू किया।

आजम खान के बहाने सपा पर चंद्रशेखर का निशाना

सौरभ वार्ष्णेय

उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 के विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही नए राजनीतिक समीकरण बनने और पुराने गठबंधनों की जमीन खिसकने की कवायद तेज हो गई है। सत्ता की इस सियासी जंग में अब असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद की जुगलबंदी ने एक नया मोर्चा खोल दिया है। यह गठबंधन महज दो राजनीतिक दलों का चुनावी समझौता नहीं, बल्कि प्रदेश की उस सामाजिक और राजनीतिक जमीन पर अपनी पकड़ बनाने की कोशिश है, जिस पर लंबे समय से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की नजर रही है। खास बात यह है कि गठबंधन की घोषणा के 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि चंद्रशेखर आजाद ने सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान को लेकर ऐसा बयान दे दिया, जिसने उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई बहस छेड़ दी।

चंद्रशेखर आजाद ने सवाल उठाया कि आजम खान किसकी वजह से जेल में हैं, यह सबको मालूम है। उन्होंने आरोप लगाया कि आजम खान का इस्तेमाल केवल मुस्लिम वोट हासिल करने के लिए किया गया और जब उनके अधिकारों की लड़ाई लडने का वक्त आया तो उनके साथ खड़े होने वाले लोग पीछे हट गए। जाहिर है कि इस बयान का निशाना समाजवादी पार्टी और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की ओर था। राजनीतिक दृष्टि से देखें तो यह बयान केवल आजम खान के प्रति सहानुभूति जताने की कोशिश नहीं, बल्कि सपा के मुस्लिम नेतृत्व और उसके राजनीतिक व्यवहार पर सवाल खड़ा करने की रणनीति भी है।

दरअसल, समाजवादी पार्टी की राजनीति में आजम खान की भूमिका किसी सामान्य नेता की नहीं रही है। वह दशकों तक पार्टी के सबसे प्रभावशाली मुस्लिम चेहरों में शामिल रहे। रामपुर और रुहेलखंड क्षेत्र में उनका अपना जनाधार रहा है। मुस्लिम मतदाताओं के बीच उनकी राजनीतिक स्वीकार्यता ने सपा को एक मजबूत सामाजिक आधार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऐसे में आजम खान की नाराजगी, राजनीतिक उपेक्षा या उनके साथ हुए व्यवहार को लेकर उठने वाले सवालों का असर केवल एक नेता तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह समाजवादी पार्टी के मुस्लिम समर्थन आधार को भी प्रभावित कर सकता है।

यही वह राजनीतिक खालीपन है, जिसे ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद अपने लिए अवसर के रूप में देख रहे हैं। दोनों नेताओं ने सामाजिक परिवर्तन मोर्चा बनाकर दलितों और मुसलमानों को एक साझा राजनीतिक मंच पर लाने का प्रयास किया है। चंद्रशेखर आजाद का मुख्यमंत्री पद का चेहरा होना भी इसी रणनीति का हिस्सा माना जा सकता है। इसके माध्यम से वह दलित समाज को यह संदेश देना चाहते हैं कि अब उसे केवल किसी बड़े राजनीतिक दल के समर्थन आधार के रूप में नहीं, बल्कि सत्ता के नेतृत्वकारी दावेदार के रूप में अपनी राजनीतिक ताकत स्थापित करनी चाहिए।

यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ओवैसी और चंद्रशेखर की जोड़ी अखिलेश यादव के पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण में सेंध लगाने में सफल हो पाएगी? समाजवादी पार्टी ने पिछले कुछ वर्षों में पीडीए को अपनी राजनीति का केंद्रीय आधार बनाया है। इस रणनीति के तहत पिछड़े वर्गों, दलितों और अल्पसंख्यकों को एक साझा राजनीतिक पहचान देकर भाजपा के मुकाबले व्यापक सामाजिक गठबंधन तैयार करने की कोशिश की गई है। लेकिन किसी भी सामाजिक गठबंधन की मजबूती केवल नारों और चुनावी घोषणाओं से तय नहीं होती, बल्कि उसके पीछे नेतृत्व, भरोसा, संगठन और राजनीतिक हिस्सेदारी



का ठोस आधार होना जरूरी है।

ओवैसी की राजनीति का प्रमुख आधार मुस्लिम मतदाताओं के बीच राजनीतिक प्रतिनिधित्व और अधिकारों का सवाल रहा है। वहीं चंद्रशेखर आजाद ने दलित राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश की है। दोनों के साथ आने से एक ऐसा राजनीतिक विकल्प सामने आ सकता है, जो मुस्लिम और दलित मतदाताओं के बीच अपनी स्वीकार्यता बढ़ाने का प्रयास करेगा। हालांकि, इस गठबंधन के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि मुस्लिम और दलित मतदाताओं को केवल भावनात्मक मुद्दों के आधार पर एक साथ लाना कितना संभव होगा। दोनों समुदायों की राजनीतिक प्राथमिकताएं, क्षेत्रीय परिस्थितियां और चुनावी अपेक्षाएं अलग-अलग भी हो सकती हैं।

आजम खान का मुद्दा इस गठबंधन के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक हथियार बन सकता है। यदि चंद्रशेखर आजाद आजम खान से मुलाकात करते हैं और उनके पक्ष में खुलकर राजनीतिक आवाज उठाते हैं, तो वह सपा के मुस्लिम समर्थकों के बीच यह संदेश देने की कोशिश करेंगे कि उनकी पार्टी मुस्लिम नेतृत्व के सम्मान और अधिकारों के सवाल पर अधिक मुखर है। लेकिन यह भी समझना होगा कि आजम खान के समर्थकों का असंतोष अपने आप किसी दूसरे राजनीतिक दल के समर्थन में परिवर्तित हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आजम खान की राजनीतिक निष्ठा, उनके समर्थकों की सोच और स्थानीय नेतृत्व की भूमिका इस पूरे समीकरण को प्रभावित करेगी। दूसरी ओर अखिलेश यादव के सामने भी इस चुनौती को हल्के में लेने की गुंजाइश नहीं है। वह पिछले महीने आजम खान से मुलाकात कर उनके प्रति अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता का संदेश दे चुके हैं और उनके खिलाफ दर्ज मामलों को राजनीतिक साजिश बता चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या इतना पर्याप्त है? सपा नेतृत्व को यह सुनिश्चित करना होगा कि पार्टी के पुराने और प्रभावशाली मुस्लिम नेताओं तथा कार्यकर्ताओं के बीच भरोसे की कमी पैदा न हो। केवल पीडीए का नारा देने से सामाजिक समीकरण मजबूत नहीं होते, इसके लिए सभी वर्गों को राजनीतिक और संगठनात्मक स्तर पर सम्मानजनक भागीदारी भी देनी पड़ती है।पश्चिमी उत्तर प्रदेश, रुहेलखंड और पूर्वांचल के कुछ हिस्सों में इस नए गठबंधन की राजनीतिक गतिविधियों पर विशेष नजर रहेगी। इन क्षेत्रों में मुस्लिम और दलित मतदाताओं की संख्या कई विधानसभा सीटों पर चुनावी परिणामों को प्रभावित करने की क्षमता रखती है। यदि ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद का मोर्चा इन मतदाताओं के बीच प्रभावी संवाद स्थापित करने में सफल होता है, तो उसका सीधा असर सपा के चुनावी गणित पर पड़ सकता है। हालांकि, इसका लाभ किसे मिलेगा, यह इस बात पर भी निर्भर करेगा कि भाजपा विरोधी मतों का विभाजन किस स्तर तक होता है।

यहां बहुजन समाज पार्टी की भूमिका को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। चंद्रशेखर आजाद के सामने दलित राजनीति में मायावती की ऐतिहासिक विरासत और उनके पारंपरिक मतदाता आधार को चुनौती देने का सवाल भी होगा। दलित समाज का एक बड़ा वर्ग अभी भी बसपा की राजनीतिक पहचान से जुड़ा हुआ है, जबकि एक हिस्सा सपा के साथ नए सामाजिक समीकरणों में अपनी संभावनाएं तलाश रहा है। ऐसे में चंद्रशेखर को केवल मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित कर देने से दलित मतदाताओं का व्यापक समर्थन मिल जाएगा, यह मान लेना राजनीतिक अपरिपक्वता होगी।

असल परीक्षा गठबंधन की संगठनात्मक क्षमता, बूथ स्तर पर मौजूदगी, उम्मीदवारों के चयन और साझा चुनावी एजेंडे की होगी। ओवैसी की भाषण शैली और चंद्रशेखर की आक्रामक राजनीतिक सक्रियता चुनावी माहौल तो बना सकती है, लेकिन उसे वोटों में बदलने के लिए मजबूत संगठन और क्षेत्रीय नेतृत्व की आवश्यकता होगी। 2027 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव केवल भाजपा और सपा के बीच सत्ता की सीधी लड़ाई नहीं रहने वाला है। इसमें छोटे दलों, सामाजिक संगठनों और नए गठबंधनों की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो सकती है। ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद की जुगलबंदी ने निश्चित रूप से अखिलेश यादव के सामने एक नई चुनौती खड़ी की है। लेकिन यह गठबंधन सपा के पीडीए फॉर्मूले को कितना नुकसान पहुंचाएगा और खुद कितना जनाधार हासिल करेगा, इसका फैसला बयानों से नहीं, जनता के भरोसे और चुनावी जमीन पर उसकी सक्रियता से होगा। फिलहाल इतना स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलित और मुस्लिम मतदाताओं को अपने साथ जोडने की लड़ाई तेज हो चुकी है। अब देखना यह है कि 2027 में यह नया सामाजिक समीकरण सत्ता परिवर्तन का आधार बनेगा या फिर विपक्षी मतों के बिखराव की एक और कहानी लिखेगा।

सवाल वोट की विश्वसनीयता का

कुमार कृष्णन

लोकतंत्र में सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि सत्ता किसके पास है, बल्कि यह है कि सत्ता तक पहुंचने का रास्ता कितना निष्पक्ष और विश्वसनीय है। चुनाव में जनता का वोट सरकार गठन का आधार होता है। यदि मतदाता सूची की शुद्धता, मताधिकार की सुरक्षा और चुनाव कराने वाली संवैधानिक संस्था की निष्पक्षता पर सवाल उठें तो यह किसी एक दल का मामला नहीं, लोकतंत्र की बुनियाद का प्रश्न है। दिल्ली के रामलीला मैदान में 1 नवंबर 2026 को आयोजित 'वोट बचाओ, देश बचाओ' रैली इसी सवाल को लेकर राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आई। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी और इंडिया गठबंधन के अनेक नेताओं का एक मंच पर आना विपक्षी एकजुटता का सार्वजनिक प्रदर्शन था। रामलीला मैदान भारतीय लोकतंत्र के संघर्षों का साक्षी रहा है। 1974 का संपूर्ण क्रांति आंदोलन पटना के गांधी मैदान से उठा था। 25 जून 1975 को जयप्रकाश नारायण ने दिल्ली के रामलीला मैदान में ऐतिहासिक सभा की थी। आपातकाल के विरोध और 1977 के राजनीतिक परिवर्तन में भी इस मैदान की भूमिका रही। इसलिए यहां जुटी भीड़ को केवल चुनावी रैली मानना पर्याप्त नहीं। इसका महत्व इस बात में है कि मताधिकार और चुनावी प्रक्रिया का सवाल फिर सार्वजनिक आंदोलन का विषय बना। किसी सभा को ऐतिहासिक रूप से सबसे बड़ी बताने के लिए प्रमाणित तुलनात्मक आंकड़े जरूरी हैं। इस आंदोलन की पृष्ठभूमि में चुनाव आयोग की ओर से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर है। विपक्ष का आरोप है कि इस प्रक्रिया में वास्तविक मतदाताओं के नाम हटाए जा रहे हैं। गरीबों, प्रवासी मजदूरों, महिलाओं और वंचित समुदायों के सामने दस्तावेजों तथा प्रक्रियागत कठिनाइयों के कारण मताधिकार से वंचित होने का खतरा पैदा हो सकता है। विपक्ष ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग भी उठाई है। दूसरी ओर चुनाव आयोग का तर्क है कि मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाने के लिए पुनरीक्षण जरूरी है और मृत, स्थानांतरित तथा दोहरी प्रविष्टियों की पहचान इसी का हिस्सा है। मूल प्रश्न है कि प्रक्रिया पारदर्शी कैसे बने और पात्र मतदाताओं के अधिकार कैसे सुरक्षित रहें। चुनाव केवल मतदान की तारीख और मतगणना का नाम नहीं है। उसकी विश्वसनीयता उस पूरी प्रक्रिया पर निर्भर करती है, जिसके माध्यम से नागरिक मतदाता बनता और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करता है। किसी पात्र नागरिक का नाम सूची से हटे तो उसे समय रहते शिकायत और सुधार का प्रभावी अवसर मिलना चाहिए। तकनीकी दक्षता के साथ मानवीय संवेदनशीलता और जवाबदेही भी जरूरी है। मतदाता सूची की त्रुटि सरकारी रजिस्टर की सामान्य गलती नहीं; उसका सीधा असर नागरिक की राजनीतिक भागीदारी पर पड़ता है। इस आंदोलन को समझने के लिए जंतर-मंतर का घटनाक्रम भी महत्वपूर्ण है। वर्षों से यह दिल्ली में जनविरोध और लोकतांत्रिक असहमति का पहचाना हुआ स्थल रहा है। 12 अक्टूबर 2026 को दिल्ली पुलिस ने इसे निर्धारित विरोध स्थल की सूची से हटाकर रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और सीबीडी मैदान को वैकल्पिक स्थल घोषित किया। यह फैसला गृह मंत्रालय की समिति की सिफारिशों के बाद आया; इससे पहले सर्वोच्च न्यायालय ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के लिए उपयुक्त वैकल्पिक स्थलों और बुनियादी सुविधाओं पर विचार करने को कहा था। सवाल है कि विरोध के लिए स्थान देना ही पर्याप्त है या उसकी पहुंच, दृश्यता और सत्ता के केंद्र तक आवाज पहुंचने की संभावना भी महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त की भूमिका पर सवाल उठाए। उन्होंने मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों को लोकतंत्र के लिए चुनौती बताते हुए कहा कि मताधिकार की रक्षा सभी नागरिकों का सवाल है। उन्होंने बड़े पैमाने पर नाम हटाए जाने का दावा किया।

सोनिया गांधी की किताब से कांग्रेस को मिलेगा सियासी फायदा?

सौरभ वार्ष्णेय

किसी भी राजनेता की किताब केवल उसके जीवन की घटनाओं का संकलन नहीं होती, बल्कि वह उसके व्यक्तित्व, विचारधारा, संघर्ष और राजनीतिक दृष्टिकोण को समझने का एक माध्यम भी होती है। कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी की किताब बिलॉन्गिंग ए जर्नी ऑफ लव' इन दिनों राजनीतिक और सामाजिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। किताब को लेकर सोशल मीडिया से लेकर समाचार माध्यमों तक बहस छिड़ी हुई है। कोई इसे सोनिया गांधी के जीवन और संघर्ष की प्रेरक कहानी बता रहा है, तो कोई इसमें लिखी बातों को राजनीतिक नजरिये से देख रहा है।

इस किताब का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसके माध्यम से देश के आम नागरिकों को सोनिया गांधी के उस व्यक्तित्व और विचारधारा को समझने का अवसर मिल सकता है, जिससे वे अब तक पूरी तरह परिचित नहीं रहे हैं। भारतीय राजनीति में सोनिया गांधी का नाम लंबे समय से चर्चा और विवादों के केंद्र में रहा है। उनके राजनीतिक जीवन का एक बड़ा हिस्सा विदेशी मूल के मुद्दे को लेकर हुए विरोध और आरोप-प्रत्यारोप के बीच गुजरा है। विपक्षी दलों ने समय-समय पर उनके विदेशी मूल को राजनीतिक हथियार बनाया और इसी मुद्दे के सहारे कांग्रेस नेतृत्व को घेरने की कोशिश की।

लेकिन सवाल यह है कि क्या किसी व्यक्ति का जन्म किसी दूसरे देश में होना ही उसके पूरे व्यक्तित्व और देश के प्रति उसके योगदान का मूल्यांकन करने का आधार होना चाहिए? सोनिया गांधी ने विवाह के



बाद भारत को अपना घर बनाया, भारतीय समाज और संस्कृति के बीच अपना जीवन बिताया और बाद में देश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके राजनीतिक निर्णयों से असहमति हो सकती है, उनके नेतृत्व की आलोचना भी की जा सकती है, लेकिन उनके जीवन और विचारों को समझे बिना केवल विदेशी मूल के आधार पर उनका मूल्यांकन करना लोकतांत्रिक बहस को सीमित करता है।

सोनिया गांधी की इस किताब की चर्चा इसलिए भी अधिक हो रही है क्योंकि उन्होंने अपने जीवन के उन अनुभवों को सार्वजनिक करने का प्रयास किया है, जिनके बारे में अब तक अलग-अलग लोगों और राजनीतिक विश्लेषकों के माध्यम से बातें सामने आती रही हैं। किताब में इटली में बचपन, राजीव गांधी से मुलाकात, विवाह के बाद भारत में जीवन, इंदिरा गांधी के साथ संबंध, परिवार में हुई दुखद घटनाओं और राजनीति में उनकी भूमिका जैसे पहलुओं को स्थान दिया गया है। सोनिया गांधी ने स्वयं भी यह कहा है कि उनके बारे में वर्षों से लिखी गई कई बातें सही नहीं थीं और वह अपनी कहानी अपने शब्दों में बताना चाहती थीं।

इस किताब के प्रकाशन से पहले ही विवाद शुरू हो गया था। पहले पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के साथ प्रकाशन को लेकर सहमति नहीं बन पाई और बाद में हार्परकॉलिन्स ने इसे प्रकाशित किया। बताया गया कि पांडुलिपि के कुछ हिस्सों में संपादकीय बदलावों को लेकर मतभेद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आरएसएस और देश की समकालीन राजनीतिक परिस्थितियों से जुड़े संदर्भ भी चर्चा में रहे। ऐसे में किताब का प्रकाशन केवल साहित्यिक घटना न रहकर राजनीतिक बहस का विषय बन गया।

किताब सामने आने के बाद भाजपा ने भी इस पर सवाल उठाए हैं। विशेष रूप से आपातकाल और 1984 के सिख विरोधी दंगों जैसे संवेदनशील ऐतिहासिक प्रसंगों को लेकर भाजपा ने सोनिया गांधी पर इतिहास को अपने पक्ष में प्रस्तुत करने का आरोप लगाया है। वहीं कांग्रेस नेताओं का कहना है कि एक व्यक्ति को अपने जीवन के अनुभव और विचार सामने रखने का अधिकार है। यहां यह भी जरूरी है कि पाठक किताब में लिखे प्रत्येक दावे को अंतिम सत्य मानने के बजाय ऐतिहासिक तथ्यों, उपलब्ध दस्तावेजों और दूसरे पक्ष के दृष्टिकोण के साथ परखें।

अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आम नागरिक इस किताब को किस नजरिये से देखेगा? क्या वह इसे एक महिला के व्यक्तिगत संघर्ष और जीवन यात्रा के रूप में पढ़ेगा या फिर इसे कांग्रेस की राजनीतिक रणनीति का हिस्सा मानेगा? निश्चित रूप से अलग-अलग पाठकों की अपनी सोच और प्राथमिकताएं होंगी। लेकिन किसी भी लोकतांत्रिक समाज में किसी नेता को अपनी बात रखने और जनता को उसे पढ़कर अपनी राय बनाने का पूरा अधिकार है।

राजनीतिक दृष्टि से देखें तो इस किताब से कांग्रेस को लाभ मिलने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। पिछले कई वर्षों से गांधी परिवार को लेकर विरोधियों ने जो राजनीतिक नैरेटिव बनाया है, उसके मुकाबले अब सोनिया गांधी को अपनी कहानी स्वयं प्रस्तुत करने का अवसर मिला है। खासकर युवा पीढ़ी, जिसने सोनिया गांधी के राजनीतिक जीवन के शुरुआती दौर को प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा, उनके संघर्ष, पारिवारिक जीवन और राजनीतिक फैसलों को नए सिरे से समझ सकती है। कांग्रेस इस अवसर का उपयोग अपने राजनीतिक इतिहास और विचारधारा को जनता तक पहुंचाने के लिए कर सकती है। हालांकि केवल किताब के चर्चित हो जाने से चुनावी लाभ सुनिश्चित नहीं हो जाता। राजनीति में जनता का फैसला भावनाओं के साथ-साथ रोजगार, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसानों की समस्याओं, राष्ट्रीय सुरक्षा और सरकार के कामकाज जैसे मुद्दों पर भी निर्भर करता है। कांग्रेस को यदि इस किताब से कोई राजनीतिक लाभ उठाना है तो उसे सोनिया गांधी के संस्मरणों से आगे बढ़कर जनता के बीच अपनी नीतियों, संगठन और भविष्य की योजनाओं को भी मजबूती से रखना होगा।

यह भी ध्यान रखना होगा कि विरोधियों की आलोचना कई बार किसी पुस्तक को और अधिक लोकप्रिय बना देती है। सोनिया गांधी की किताब के साथ भी कुछ ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है। जिस पुस्तक को पाठकों तक पहुंचने में सामान्य प्रकाशन प्रक्रिया से गुजरना था, वह प्रकाशन से पहले ही राजनीतिक विवाद का हिस्सा बन गई।

हिंदू वोटरों के नाम जुड़वाने के लिए मैदान में उतरी पूरी भाजपा

नीरज कुमार दुबे

उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की लड़ाई अब सिर्फ राजनीतिक रैलियों, जातीय समीकरणों और सत्ता विरोधी लहर तक सीमित नहीं रहने वाली। चुनावी मुकाबले का एक नया मोर्चा खुल गया है और यह मोर्चा है मतदाता सूची का। बीजेपी ने हिंदू मतदाताओं के वोटर लिस्ट से गायब हुए नामों को दोबारा जुड़वाने के लिए जिस तरह की संगठनात्मक तैयारी शुरू की है, उसने साफ कर दिया है कि पार्टी 2027 की लड़ाई को लेकर कोई जोखिम उठाने के मूड में नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मुद्दे को जिस गंभीरता से उठाया है, उसके बाद बीजेपी का पूरा संगठन मैदान में उतरने की तैयारी कर रहा है।

हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण (स्क्रुक्र) के दौरान करीब 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से बाहर होने का दावा सामने आने के बाद बीजेपी ने अपने नेताओं को इन नामों को वापस जुड़वाने का लक्ष्य सौंपा है। पार्टी ने तय किया है कि अगले एक महीने तक दूसरे राजनीतिक कार्यक्रमों के बजाय मतदाता सूची को दुरुस्त कराने पर पूरा जोर लगाया जाएगा। इसके लिए जिला अध्यक्षों से लेकर बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं तक को सक्रिय किया जा रहा है।

देखा जाये तो यह महज नाम जुड़वाने का अभियान नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति में वोटों की ताकत को नए सिरे से व्यवस्थित करने की कवायद है। बीजेपी नेतृत्व को अच्छी तरह मालूम है कि विधानसभा चुनाव में कई बार जीत और



हार का फैसला हजार-दो हजार वोटों से होता है। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी पार्टी ने कई सीटें महज 1,500 से 3,000 वोटों के अंतर से जीती थीं। ऐसे में अगर किसी विधानसभा क्षेत्र में पांच से दस हजार मतदाताओं के नाम सूची से गायब हो जाएं तो चुनावी गणित पूरी तरह बदल सकता है।

यही वजह है कि बीजेपी ने हर विधानसभा क्षेत्र में 10 हजार से 25 हजार पात्र मतदाताओं के नाम दोबारा जुड़वाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसका मतलब है कि हर मतदान केंद्र पर कम से कम 50 मतदाताओं तक पहुंच बनाई जायेगी। पार्टी के एक नेता के मुताबिक, यदि 40 लाख से 80 लाख मतदाताओं के नाम भी दोबारा जुड़वा दिए जाते हैं तो यह चुनावी दृष्टि से पर्याप्त साबित हो सकता है।

हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अभियान को %अंतिम मौका% बताते हुए नेताओं को पूरी ताकत लगाने का संदेश दिया है। शुक्रवार को लखनऊ में हुई बीजेपी की बैठक में मुख्यमंत्री के साथ उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी भी मौजूद रहे। बैठक में जिला अध्यक्षों और प्रभारियों को साफ संदेश दिया गया कि अब संगठन की प्राथमिकता मतदाता सूची में छूटे हुए पात्र मतदाताओं को वापस लाना है।

देखा जाये तो इस अभियान की सबसे दिलचस्प बात इसकी चुनावी रणनीति है। बीजेपी केवल मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की औपचारिकता नहीं करना चाहती, बल्कि उन विधानसभा क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने जा रही है जहां हिंदू मतदाताओं के नाम अधिक संख्या में हटे हैं और जहां इन नामों की वापसी से पार्टी की जीत की संभावनाएं मजबूत हो सकती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, मुस्लिम बहुल उन सीटों पर पार्टी विशेष जोर नहीं देना चाहती जहां वह पहले से चुनावी मुकाबले में कमजोर रही है।

साथ ही बीजेपी की रणनीति में शहरी मतदाता भी महत्वपूर्ण हैं। पार्टी का आकलन है कि स्क्रुक्र के दौरान बड़ी संख्या में शहरी मतदाताओं ने अपने नाम ग्रामीण क्षेत्रों के पते पर स्थानांतरित करा लिए। इससे शहरी सीटों पर पार्टी के पारंपरिक वोट बैंक का चुनावी प्रभाव प्रभावित हो सकता है। ऐसे मतदाताओं को वापस शहरी विधानसभा क्षेत्रों की सूची में शामिल कराने की कोशिश होगी। दूसरे राज्यों में चले गए और वहां मतदाता के रूप में पंजीकृत हो चुके लोगों से भी संपर्क किया जाएगा। इसके अलावा महिलाओं और पहली बार वोट डालने वाले युवाओं के नाम जुड़वाने पर विशेष जोर रहेगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पंचायत चुनाव की मतदाता सूची और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों की सूची से विधानसभा मतदाता सूची का मिलान कराने का निर्देश भी दिया है। मुख्यमंत्री का दावा है कि पंचायत मतदाता सूची में मौजूद 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम विधानसभा मतदाता सूची में नहीं हैं। उन्होंने यह सवाल भी उठाया है कि आखिर ये नाम गायब कैसे हुए?

दरअसल, उत्तर प्रदेश में स्क्रुक्र के बाद मतदाताओं की संख्या 15.44 करोड़ से घटकर 13.39 करोड़ रह गई है। अब 17 नवंबर को विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की प्रारूप मतदाता सूची जारी होने वाली है। इसके बाद 16 दिसंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी। बीजेपी 20 नवंबर से अपने कार्यकर्ताओं और बूथ लेवल एजेंटों को मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है।

देखा जाये तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में बीजेपी का यह अभियान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 2027 का चुनाव केवल सरकार के कामकाज का मूल्यांकन नहीं होगा, बल्कि हर विधानसभा क्षेत्र में वोटों के बारीक गणित का मुकाबला भी होगा। पार्टी जानती है कि चुनाव जीतने के लिए बड़े राजनीतिक नारों के साथ-साथ बूथ पर मौजूद हर एक वोट की अहमियत है। बहरहाल, योगी आदित्यनाथ ने जिस मुद्दे को उठाया, बीजेपी संगठन ने उसे सीधे चुनावी अभियान में बदलने का फैसला कर लिया है। अब पार्टी की नजर लखनऊ से लेकर गांवों की गलियों तक और जिला मुख्यालयों से लेकर हर मतदान केंद्र तक है। 2027 की सत्ता की लड़ाई में बीजेपी का संदेश है कि वोटर लिस्ट में अपने समर्थक मतदाताओं का एक भी नाम छूटने नहीं देना है।

अमेरिका मध्यावधि चुनाव में ट्रम्प की पराजय

राजेश बादल

हिंदुस्तान का एक बड़ा वर्ग मुदित है कि अमेरिका के मध्यावधि चुनाव में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की पराजय हुई और वे पहले की तुलना में ज्यादा बौने हो गए। अनेक भारतीय जानकार ट्रम्प की हार के बाद इस आधार पर विश्लेषण कर रहे हैं कि अब भारत के ऊपर छाया घटाटोप अंधकार जैसे दूर हो गया है और यह विश्व-चौधरी भारत को लेकर अपनी नीतियां बदल देगा। पर शायद वे गहराई से मंथन नहीं कर रहे हैं। राष्ट्रपति के रूप में अभी भी डोनाल्ड ट्रम्प के दो बरस बाकी हैं। अपने शेष कार्यकाल में ट्रम्प भारत को लेकर अधिक खूंखार नहीं हो जाएंगे, इसकी क्या गारंटी है? भले ही चुनाव के बाद उनके नाखून और दांत तोड़ दिए गए हों, पर अमेरिकी संविधान के मुताबिक अभी भी उनके पास शक्तियों का एक अथाह भंडार सुरक्षित है। ईरान के साथ जंग रोकने से और यूरोपीय यूनियन से दूरी से अमेरिका की आर्थिक बदहाली पर निश्चित रूप से अंकुश लगता है। लेकिन हिंदुस्तान के प्रति उनकी कोप दृष्टि अमेरिका को कोई ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती। अलबत्ता आने वाले दिनों के लिए भारत को स्पष्ट चेतावनी देती है कि उसे ट्रम्प की नीतियों से अधिक सतर्क और सावधान रहना होगा। अब भारत के पड़ोस में अमेरिका, पाकिस्तान और बांग्लादेश का उभरता त्रिकोण खतरे की घंटी बजा रहा है। चीन तो सिर पर एक तटस्थ शत्रु की भूमिका में है ही। अमेरिकी इशारे पर ही पाकिस्तान ने मक्का गठबंधन बनाया है। ऐसा कोई गठबंधन अभी भारत के पास नहीं है, जो यह कहता हो कि भारत पर इन देशों ने आक्रामक कार्रवाई की तो कोई अन्य देश उसे अपने पर आक्रमण मानेगा। ले-देकर भूटान, नेपाल और श्रीलंका ही ऐसे देश हैं, जिनके बल पर भारत उछल सकता हो। मगर इन देशों की संयुक्त ताकत का क्या अर्थ है। म्यांमार का फौजी शासन भी चीन के ज्यादा करीब है। आपको याद होगा कि एक जमाने में भारत ने पाकिस्तान के चारों ओर अफगानिस्तान, ईरान, इराक, रूस और दूसरे छोर पर बसे बांग्लादेश के माध्यम से ऐसी घेराबंदी की थी कि पाकिस्तान के लिए उससे बाहर आना कठिन था। वह इस घेराबंदी से घबराया हुआ था। इसीलिए उसने चीन और अमेरिका की गोद में बैठना हमेशा पसंद किया। वैसे भारत के विरुद्ध अमेरिका का पाकिस्तान को समर्थन तो 1947 से ही मिलता रहा है। उसने हमेशा अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान को समर्थन देना जारी रखा। भारत उसके लिए एक ऐसी ताकत था जो कभी भी उसके समानांतर खड़ा होकर आंखों में आंखें डालकर बात करने का साहस कर सकता था। भारत को इस कुटिल गठबंधन का मुकाबला करने के लिए रूस (तत्कालीन सोवियत संघ) से मैत्री की एक स्वाभाविक परंपरा डालनी पड़ी थी। यह स्थिति एशिया में एक ऐसा शक्ति संतुलन बनाती थी कि कोई भी देश एक-दूसरे की सार्वभौमिकता पर चढ़ाई नहीं कर सकता था। मगर इन दिनों हालात बदले हुए हैं। पलड़ा अमेरिका के पक्ष में झुका है। पाकिस्तान में इमरान खान और बांग्लादेश में शेख हसीना वाजेद की सरकारों का तख्तापलट अमेरिकी इशारे पर हुआ था - यह तथ्य छिपा हुआ नहीं है। अब दोनों मुल्कों की हुकूमतें अमेरिका के पक्ष में खड़ी दिखाई देती हैं। इन दोनों राष्ट्रों की भौगोलिक, सामाजिक और अंदरूनी सियासी स्थितियों का लाभ भी उसे मिल रहा है। इसीलिए भारत में भी जब-तब वह अस्थिरता पैदा करने की अप्रत्यक्ष कोशिश करता रहा है।

सर्दियों में बच्चों को रहता है इन 4 बीमारियों का खतरा, ऐसे करें बचाव



ठंड के इस मौसम में इम्यूनिटी कमजोर होने लगती है। इम्यूनिटी कमजोर होने के कारण शरीर वायरल समस्याओं से बहुत ही जल्दी घिरता है। खासतौर पर छोटे बच्चों की इम्यूनिटी कमजोर ही रहती है। ऐसे में बच्चों को कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं से इस मौसम में जूझना पड़ता है। सर्दियों में बच्चों को सांस से जुड़ी समस्याएं भी बहुत ही जल्दी परेशान करती हैं इसके कारण बच्चों के गले में खराश, नाक बहना और सर्दी खांसी जैसे लक्षण आम होते हैं। कुछ बच्चों को थकान और सुस्ती भी इसके कारण महसूस होती है।

निमोनिया

इस समस्या के कारण बच्चे सर्दियों में परेशान हो सकते हैं। यह बीमारी बच्चों में सर्दियों में ज्यादा देखने को मिलती है। यह सांस से जुड़ी एक ऐसी समस्या है जो फेफड़ों को प्रभावित करती है। इस स्थिति में बच्चों को सांस लेने में परेशानी होती है। यह बैक्टीरिया या फिर कवक के कारण हो सकता है। निमोनिया बच्चों को सर्दियों में ज्यादा परेशान करता है हालांकि यह व्यस्कों को भी हो सकता है।

साइनस

यह समस्या हर उम्र के लोगों के देखने में मिलती है। बच्चों को साइनस हो सकता है। इस समस्या में नाक और आंख के पीछे हवा से भरी थैलियों में द्रवा जमा हो जाता है जिससे संक्रमण का खतरा रहता है। बच्चों को साइनस होने के कारण सिरदर्द, बुखार, सर्दी-जुकाम जैसे लक्षण भी दिखते हैं। यदि आपके बच्चों को साइनस की बीमारी है तो सर्दियों में आपको उनका ज्यादा ध्यान रखने की जरुरत होती है।

अस्थमा

यह बीमारी सर्दियों में ज्यादा बढ़ती हैं। बच्चों को भी अस्थमा हो सकता है। यह बीमारी फेफड़ों को वायुमार्ग को संकरा कर देता हैं। इससे बच्चों को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। इसके कारण बच्चों को सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। इससे कफ की समस्या भी होती है और बच्चों को घबराहट भी हो सकती है। ऐसे में सर्दी के मौसम में आपको बच्चों की धूल-मिट्टी और प्रदूषण से बचाना चाहिए।

ब्रोंकियोलाइटिस

यदि सर्दियों में आपके बच्चे को बार-बार सर्दी-खांसी होती है तो यह ब्रोंकियोलाइटिस का संकेत भी हो सकता है। यह शिशुओं और बच्चों को प्रभावित करने वाली बीमारी हो जो फेफड़ों में वायुमार्ग में सूजन का कारण बन सकता है। यह एक संक्रामक बीमारी है जो खांसी या छींक के माध्यम से निकलने वाली बूंदों के संपर्क में आने से फैलता है। इस स्थिति में बच्चों को नाक बहना, बुखार या फिर सीने में घरघराहट जैसे लक्षणों का सामना भी करना पड़ सकता है।



बच्चों का कैसे करें बचाव?

.सांस की बीमारियों से बच्चों को बचाने के लिए हाइजीन का खास ध्यान रखें।
.खाना खाने से पहले बच्चों के हाथ साबुन से धुलाएं।
. यदि बच्चों को खांसी हो रही है तो खांसते हुए और छींकते हुए मुंह ढकने के लिए कहें।
.ठंड से बचाने के लिए बच्चों को पूरे कपड़े पहनाएं। बच्चों को दस्ताने और मास्क भी जरुर पहनाएं।
.भीड़-भाड़ वाली जगहों पर बच्चों को न जाने दें।
.बच्चे के खान-पान का ध्यान रखें।

शरीर को गरम रखें

अक्सर बच्चों को ठंड लगने की वजह से, वे बुखार और खांसी-जुकाम का शिकार हो सकते हैं। इसलिए उन्हें अच्छे से कपड़े पहना कर रखें। अक्सर बच्चे जुराब और टोपी नहीं पहनते, जिस वजह से उन्हें ठंड लग जाती है। इसलिए कोशिश करें कि उन्हें ठीक से कपड़े पहनाएं और ठंड से बचा कर रखें।

हाइजीन का ध्यान रखें

सर्दियों के मौसम में अक्सर बच्चे ठंड की वजह से अपनी हाइजीन का ख्याल नहीं रखते। वे गंदे हाथों से अपने मुंह और नाक को छूते हैं, जिस वजह से, वे आसानी से वायरस और बैक्टीरिया की चपेट में आ सकते हैं। इसलिए बच्चों को हाइजीन का महत्व समझाएं और हमेशा बाहर से आने के बाद अच्छे से साबुन से हाथों को धोने की सलाह दें और गंदे हाथों से मुंह न छूने दें।



संतुलित आहार खिलाएं

पोषक तत्वों की कमी की वजह से बच्चों का इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है और वे बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। इसलिए अपने बच्चों की डाइट का खास ख्याल रखें। उन्हें संतुलित आहार दें।

बीमार लोगों से दूर रखें

सर्दी और जुकाम ऐसी बीमारियां हैं, जो बीमार व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्तियों में फैल सकता है। ऐसे में बच्चे उनका आसान शिकार हो सकते हैं। इसलिए अपने बच्चों को बीमार व्यक्तियों के पास न जाने दें।

छींकते वक्त मुंह ढकें

छींकते और खांसते वक्त हवा में मुंह और नाक से ड्रॉपलेट्स आते हैं, जिनकी वजह से इन्फेक्शन फैल सकता है। इसलिए बच्चों में आदत डालें कि हमेशा छींकते या खांसते वक्त अपने मुंह और नाक को रुमाल या कोहनी से ढकें, ताकि वायरस और बैक्टीरिया हवा में न फाइलें।

पानी की कमी न होने दें

पानी की कमी की वजह से म्यूकस लाइनिंग मोटी होने लगती है, जिस वजह से रेस्पिरेशन में तकलीफ हो सकती है और बलगम इकट्ठा हो सकता है। इसलिए बच्चों को भरपूर मात्रा में पानी पिलाएं, ताकि म्यूकस की परत मोटी न हो।

एआई के जमाने में टिके रहने के लिए हर पैरेंट अपने टीनेज बच्चों को सिखाएं ये 3 स्किल्स



आज की दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि आने वाले कुछ सालों में कई नौकरियां पूरी तरह बदल जाएंगी। ऐसे में माता-पिता के लिए ज़रूरी है कि वे अपने बच्चों को सिर्फ़ अच्छे मार्क्स नहीं, बल्कि ऐसी स्किल्स सिखाएं जो मशीनें नहीं सीख सकतीं। जानिए 3 ज़रूरी जॉब स्किल्स जो हर पैरेंट को अपने टीनेज बच्चों को सिखानी चाहिए, ताकि वे भविष्य के करियर में सफल रह सकें।

क्रिटिकल थिंकिंग - सोचने और सवाल करने की कला

एआई डेटा से फैसले ले सकता है, लेकिन सोचने, तर्क करने और सही-गलत समझने की क्षमता सिर्फ इंसानों के पास होती है।बच्चों को सिखाएँ कि वे हर जानकारी पर आंख मूंदकर भरोसा न करें, खुद से सवाल करें जैसे- क्यों?, कैसे?, क्या इसका और कोई तरीका हो सकता है? किसी समस्या को अलग-अलग दृष्टिकोण से देखें। उन्हें समाचारों या सोशल मीडिया पोस्ट पर चर्चा करने को कहें और तर्क पूछें 'तुम्हें क्यों लगता है ये सही है?'

कम्युनिकेशन और इमोशनल इंटेलिजेंस

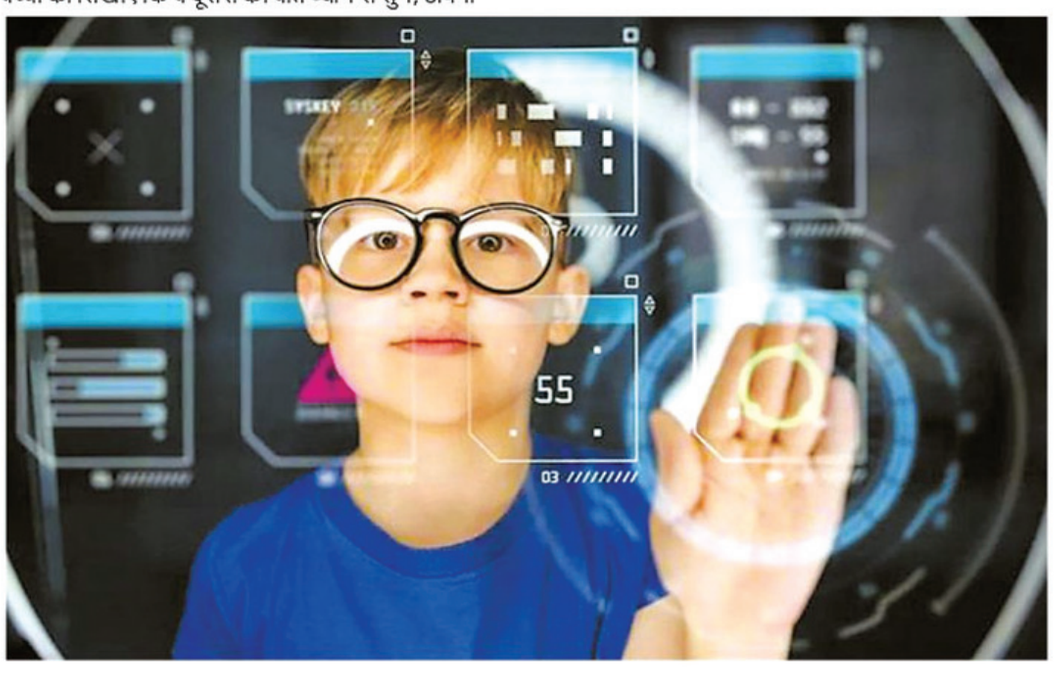
एआई चैट कर सकता है, लेकिन भावनाएं समझ नहीं सकता। भविष्य में जो इंसान दूसरों से जुड़ना, टीम में काम करना और सहानुभूति दिखाना जानता है, वही आगे बढ़ेगा। बच्चों को सिखाएं कि वे दूसरों की बात ध्यान से सुनें, अपनी भावनाएं साफ़ और सम्मानजनक तरीके से व्यक्त करें, दूसरों की स्थिति को समझने की कोशिश करेंञ उन्हें ग्रुप एक्टिविटीज़, वॉलंटियर वर्क या स्कूल डिबेट में हिस्सा लेने को प्रेरित करें।

क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग

एआई पुराने डेटा पर चलता है, लेकिन नई सोच और नए आइडिया इंसानों से ही आते हैं। क्रिएटिव बच्चे हर बदलते दौर में अपने लिए नए मौके बना लेते हैं। बच्चों को सिखाएं कि वे असफलता से डरें नहीं, बल्कि उससे सीखें, हर समस्या को एक 'पज़ल' की तरह देखें,कला, संगीत, डिजाइन या इनोवेशन जैसे क्षेत्रों में अपनी रुचि आज़माएं।उन्हें घर के छोटे प्रोजेक्ट्स सुलझाने का मौका दें - जैसे कोई टूटी चीज़ ठीक करना, बजट बनाना या कोई नया आइडिया ट्राय करना।

जरूरी बात

भविष्य उन्हीं का होगा जो सोच सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और नई दिशा बना सकते हैं। इसलिए बच्चों को सिर्फ़ एआई से डरना नहीं, बल्कि एआई के साथ आगे बढ़ना सिखाए। ध्यान रखें कि मशीनें काम कर सकती हैं, लेकिन सोचने का काम इंसान का ही रहेगा।





बच्चों के पढ़ाई और संस्कारों के साथ सिखा दें ये बातें भी, हमेशा बचे रहेंगे गलत संगत से

आज के समय में बच्चों को सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, बल्कि जीवन के संस्कार और सुरक्षा के गुण भी सिखाना बेहद जरूरी है। ऐसे बच्चे न केवल समझदार बनते हैं बल्कि बुरे लोगों या गलत संगति से खुद को बचाना भी जानते हैं। यहाँ कुछ जरूरी बातें हैं जो हर पैरेंट्स को अपने बच्चों को सिखानी चाहिए

'ना' कहना सिखाएं

बच्चों को यह समझाएं कि अगर कोई व्यक्ति उन्हें असहज महसूस कराता है चाहे वो कोई जान-पहचान वाला ही क्यों न हो तो वे तुरंत 'ना' कहें। ये आत्म-सुरक्षा का पहला कदम है। ना कहना गलत नहीं, अपनी सुरक्षा जरूरी है।

अच्छे और बुरे स्पर्श की समझ

बच्चे को सिखाएं कि शरीर के कौन से हिस्से 'प्राइवेट' हैं और वहां कोई छूए तो उसे तुरंत बताना चाहिए।इसके लिए कहानी या चित्रों के माध्यम से सिखाना आसान होता है।

खुलकर बात करना

बच्चों को डरने नहीं बोलने की हिम्मत दें। अगर स्कूल, बस, या बाहर कुछ गलत लगे तो वे तुरंत मां-पापा को बताएं।जो बच्चा अपने माता-पिता से खुलकर बात करता है, वो कभी शिकार नहीं बनता। उन्हें समझाएं कि किसी अजनबी से गिफ्ट, खाना या लिफ्ट न लें। अगर कोई अनजान व्यक्ति बुलाए, तो तुरंत भरोसेमंद बड़े को बताएं।

ऑनलाइन सुरक्षा

आजकल खतरे सिर्फ बाहर नहीं,इंटरनेट पर भी हैं। बच्चों को सिखाएं कि अपनी फोटो, लोकेशन या जानकारी किसी से साझा न करें। पैरेंट्स को भी बच्चों की ऑनलाइन एक्टिविटी पर नज़र रखनी चाहिए।

भरोसे का रिश्ता बनाए रखें

बच्चा तभी सच बोलेगा जब उसे लगेगा कि आप डांटेंगे नहीं, समझेंगे। मां-बाप का भरोसा बच्चे की सबसे बड़ी ढाल होता है। जो बच्चे इन बातों को समझते हैं, उन पर कभी बुरे लोगों का साया नहीं पड़ता। वे साहसी, समझदार और सुरक्षित बनते हैं।

'कश्मीर से कन्याकुमारी मिलेट रन' पोषण का संदेश देने निकले अल्ट्रा मैराथन रवि कुमार

नई दिल्ली। कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश को फिटनेस और पारंपरिक पोषण का संदेश देने निकले अल्ट्रा-मैराथन धावक एवं 2006 हांगकांग ओपन कराटे चैंपियनशिप के स्वर्ण पदक विजेता के. रवि कुमार दिल्ली पहुंच गए हैं। श्रीनगर के ऐतिहासिक लाल चौक से 27 अक्टूबर को शुरू हुई उनकी 'कश्मीर से कन्याकुमारी मिलेट रन' का उद्देश्य लोगों को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के साथ पारंपरिक मोटे अनाज के पोषण महत्व के प्रति जागरूक करना है। इस राष्ट्रीय अभियान के तहत रवि कुमार प्रतिदिन औसतन 50 किलोमीटर दौड़ लगाते हुए देश के विभिन्न शहरों और कस्बों से गुजर रहे हैं। इस दौरान वे विद्यार्थियों, खिलाड़ियों, आम नागरिकों और सामाजिक संगठनों से संवाद कर फिटनेस, संतुलित खानपान और बीमारियों से बचाव के प्रति जागरूकता फैला रहे हैं। अभियान का प्रमुख उद्देश्य पद्मश्री से सम्मानित और 'भारत के मिलेट मैन' के नाम से पहचान रखने वाले डॉ. खादर वली के मिलेट प्रोटोकॉल का प्रचार-प्रसार करना भी है। यह प्रोटोकॉल ज्वार, बाजरा, रागी सहित पारंपरिक मोटे अनाजों को दैनिक भोजन में शामिल करने पर जोर देता है। रवि कुमार का कहना है कि बदलती जीवनशैली के बीच लोगों को अपने पारंपरिक खानपान और शारीरिक सक्रियता की ओर लौटने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यह यात्रा केवल दौड़ नहीं, बल्कि स्वस्थ और सशक्त भारत का संदेश जन-जन तक पहुंचाने की पहल है।



मोटे अनाज पोषक तत्वों और रेशे से भरपूर होने के साथ कम संसाधनों में उगाए जा सकते हैं। ऐसे में इन्हें भोजन का हिस्सा बनाने से बेहतर पोषण और टिकाऊ कृषि को भी बढ़ावा मिल सकता है। रवि कुमार ने स्थानीय नागरिकों, धावकों, फिटनेस प्रेमियों, शिक्षण संस्थानों और स्वास्थ्य संगठनों से इस अभियान से जुड़ने की अपील की है।

पहली बार मां के गर्भ में ही बच्चे की रीढ़ की हड्डी की हुई सर्जरी

नई दिल्ली। एम्स नई दिल्ली ने गर्भावस्था के 25वें सप्ताह में लुंबोसैक्रल मायलोमेनिंगोसील के लिए भारत की पहली ओपन फीटल रिपेयर सर्जरी की है। यह स्पाइना बिफिडा% का सबसे गंभीर रूप है। 6 घंटे तक चली इस सर्जरी में, गर्भाशय के अंदर ही लुंबोसैक्रल डिफेक्ट (रीढ़ की हड्डी का दोष) को ठीक किया गया, जहां से सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड (मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी का द्रव) लीक हो रहा था। इस सर्जरी से पहले पांच सप्ताह से अधिक समय तक कई विभागों के विशेषज्ञों ने मिलकर विस्तृत योजना बनाई, जिसमें भ्रुण की बारीकी से इमेजिंग, परामर्श, एनेस्थीसिया की तैयारी और सर्जरी का पूर्वाभ्यास शामिल था। मरीज की जांच और परामर्श सबसे पहले मैटरनल-फीटल मेडिसिन टीम की प्रोफेसर के. अपर्णा शर्मा ने किया, जिसमें उनके साथ डॉ. अनुभूति राणा, डॉ. दीपाली गर्ग और डॉ. सलोनी कंबोज भी शामिल थीं। सर्जरी से पहले की योजना बनाने में रेडियोडायग्नोसिस और इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी विभाग की डॉ. स्मिता मनचंदा ने महत्वपूर्ण सहयोग दिया। यह जटिल सर्जरी एम्स नई दिल्ली के न्यूरोसाइंसेज सेंटर में की गई, जिसमें अत्याधुनिक माइक्रोस्कोपी और लगातार अल्ट्रासोनोग्राफी की मदद ली गई।



डॉक्टरों की टीम

न्यूरोसर्जरी टीम का नेतृत्व प्रोफेसर दीपक गुप्ता ने किया; मैटरनल-फीटल मेडिसिन और प्रसूति विभाग की टीम का नेतृत्व प्रोफेसर नीना मल्होत्रा और प्रोफेसर के. अपर्णा शर्मा ने किया; प्रसूति और न्यूरो-एनेस्थीसिया टीम का नेतृत्व प्रोफेसर विमी रेवारी, प्रोफेसर मिहिर पांडिया, डॉ. रश्मि रामचंद्रन और डॉ. ज्ञानेंद्र पाल सिंह ने किया; प्लास्टिक सर्जरी टीम का नेतृत्व डॉ. शशांक चौहान ने किया; और नियोनेटोलॉजी (नवजात शिशु चिकित्सा) टीम में डॉ. रमेश अग्रवाल और डॉ. दीपिका कैंथ शामिल थे।

इंडियन सोसाइटी फॉर पीडियाट्रिक न्यूरोसर्जरी के अध्यक्ष, प्रोफेसर दीपक गुप्ता ने कहा- यह भारत में भ्रुण देखभाल (फीटल केयर) और पीडियाट्रिक न्यूरोसर्जरी के लिए एक महत्वपूर्ण नई क्षमता स्थापित करता है।

सावधानीपूर्वक चुने गए मामलों में, जन्म-पूर्व (प्रीनेटल) मरम्मत का उद्देश्य खुले न्यूरल टिश्यू को होने वाले नुकसान को सीमित करना, हाइड्रोसेफालस के लिए सेरेब्रोस्पाइनल-फ्लूइड डायवर्जन (CSF डायवर्जन) की भविष्य में पड़ने वाली जरूरत को कम करना और कुछ न्यूरोलॉजिकल परिणामों में सुधार करना है।

निगरानी प्रणाली की आवश्यकता पर जोर

इस प्रक्रिया में प्रसूति एवं स्त्री रोग, मैटरनल-फीटल मेडिसिन, न्यूरोसर्जरी, एनेस्थीसिया, प्लास्टिक सर्जरी, रेडियोडायग्नोसिस और नियोनेटोलॉजी विभागों के 30 से अधिक डॉक्टरों और नर्सों ने हिस्सा लिया। मायलोमेनिंगोसील एक ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, जिसमें रीढ़ की हड्डी और उसकी परतें, रीढ़ में बने एक छेद के जरिए बाहर निकल आती हैं। भारत में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के मामले काफी अधिक हैं, हालांकि अलग-अलग भौगोलिक क्षेत्रों में इनकी संख्या अलग-अलग हो सकती है। 27 भारतीय अध्ययनों की 2024 की एक व्यवस्थित समीक्षा (सिस्टमैटिक रिव्यू) में, प्रति 1,000 जन्मों पर इनकी व्यापकता (प्रिवेलेंस) 9.46 आंकी गई है। साथ ही, इसमें एक मजबूत राष्ट्रीय निगरानी प्रणाली की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया है।

गोधरा कांडः मुस्लिम अधिकारियों ने निभाई अहम भूमिका

नई दिल्ली। साल 2002 के गोधरा ट्रेन अग्निकांड की जांच करने वाले सीबीआई के पूर्व विशेष निदेशक राकेश अस्थाना ने शनिवार को दावा किया कि उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी ने जांच के लिए उन्हें मुस्लिम पुलिस अधिकारी उपलब्ध कराए थे। एएनआई को दिए एक इंटरव्यू में अस्थाना ने कहा कि जांच के दौरान उन पर किसी तरह का राजनीतिक दबाव नहीं था। राकेश अस्थाना ने कहा, %मैं यह बताना चाहूंगा कि शुरुआती जांच में मैंने देखा कि जिस इलाके में यह घटना हुई थी, वहां पूरी तरह मुस्लिम आबादी रहती थी। ऐसे में मुस्लिम इलाके में जांच करने के लिए व्यावहारिक और पेशेवर तौर पर मुस्लिम अधिकारियों की जरूरत थी। मैंने उनसे जांच टीम में शामिल करने के लिए कुछ मुस्लिम अधिकारी देने का अनुरोध किया था। उन्होंने बताया कि इन अधिकारियों ने जांच में बेहद अहम भूमिका निभाई। अस्थाना ने एक घटना का जिक्र करते हुए बताया कि दो मुस्लिम कांस्टेबल करीब डेढ़ महीने तक गुप्त रूप से चूड़ियां और साड़ियां बेचने वाले बनकर रहे।



सरकार ने दी थी पूरी छूट

राकेश अस्थाना ने कहा कि उन्हें अपनी पसंद के वकील चुनने और सुप्रीम कोर्ट में राज्य का पक्ष रखने के लिए सबसे महंगे वकील को नियुक्त करने तक की छूट थी। अस्थाना के मुताबिक, आरोपपत्र दाखिल करने जितना ही जरूरी अदालत में आरोपियों को दोषी साबित करना भी था। अस्थाना ने कहा कि अगर जांच में जुटाए गए सबूत मजबूत नहीं होते, तो अदालतें पुलिस की जांच में खामियां निकालतीं। उन्होंने कहा कि अदालत के फैसलों से साबित होता है कि जांच में कोई दखल नहीं दिया गया और पूरी निष्पक्षता बरती गई। गोधरा ट्रेन अग्निकांड मामले में 2011 में एक विशेष अदालत ने 31 लोगों को दोषी ठहराया था।

एक-दो नहीं, महिला ने रचाईं 9 शादियां!

कर्नाटक। कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक बेहद चौंकाने वाले मामले में 9 शादियां करने वाली महिला के सातवें पूर्व पति को बड़ी राहत देते हुए उसके खिलाफ दर्ज क्रूरता, मारपीट और आपराधिक धमकी के मुकदमे को रद्द कर दिया है। न्यायमूर्ति एम. नागप्रसन्ना की पीठ ने याचिकाकर्ता राजा हुसैन की याचिका स्वीकार करते हुए 4 नवंबर को यह महत्वपूर्ण आदेश पारित किया। मामले के अनुसार, शिकायतकर्ता महिला ने साल 2022 में राजा हुसैन के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत विवाहित महिला के प्रति क्रूरता, स्वेच्छा से चोट पहुंचाने, अपमान करने और आपराधिक धमकी देने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था। हालांकि, सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि महिला अब तक नौ शादियां कर चुकी है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि मुकदमा शुरू करने से जुड़ी परिस्थितियां और शिकायत में लगाए गए आरोप याचिकाकर्ता की इस दलील को मजबूती देते हैं कि यह कानूनी कार्यवाही किसी गुप्त या अनुचित उद्देश्य की पूर्ति के लिए शुरू की गई थी।



दोनों पक्षों के दावे

कार्यवाही को रद्द कराने की मांग करते हुए, हुसैन ने तर्क दिया कि उनकी पूर्व पत्नी ने पहले भी कई शादियां की थीं। उन्होंने आरोप लगाया कि वह परिवारों में दरार पैदा करती थी, मुकदमे दर्ज कराती थी और फिर पैसों के लिए समझौता कर लेती थी। हुसैन का आरोप है कि 30 साल की इस महिला ने नौ बार शादी की थी और हर रिश्ते में उसने इसी तरह का तरीका अपनाया था। महिला ने इस याचिका का विरोध करते हुए कहा कि हुसैन के खिलाफ चल रही कार्यवाही को रद्द नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि उसके पास दहेज की मांग को लेकर क्रूरता करने के पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। उसने यह भी स्वीकार किया कि अतीत में उसकी कई बार शादी हो चुकी है।

करोड़ों साल पुराने डायनासोर के जीवाश्म में मिले रक्त के अवशेष

ब्रासीलिया। ब्राजील में पाए गए 11.5 करोड़ साल पुराने डायनासोर के जीवाश्म में रक्त के अवशेष मिले हैं। इससे डायनासोर के करोडों साल पुराने इतिहास को समझने में मदद मिलने की संभावना जताई जा रही है। शोधकर्ता वैज्ञानिकों द्वारा की गई इस विस्तृत जांच में हीमोग्लोबिन से संबंधित हीम घटक के रासायनिक प्रमाण और लाल रक्त कोशिकाओं जैसी सूक्ष्म जैविक संरचनाएं हड्डियों के भीतर पाई गई हैं। इतिहास में यह पहली बार है जब जीवाश्म बन चुकी हड्डियों की गहराई में हीमोग्लोबिन से जुड़े रासायनिक सबूत सुरक्षित अवस्था में मिले हैं। यह ऐतिहासिक खोज अरातासॉरस म्यूजियोनैशनली नामक एक छोटे थेरोपोड डायनासोर के जीवाश्म की सूक्ष्म जांच के दौरान हुई। यह डायनासोर अर्ली क्रेटेशियस काल में पृथ्वी पर मौजूद था। शारीरिक संरचना के अनुसार, यह लगभग 10 फीट लंबा और



75 पाउंड वजन का एक युवा मांसाहारी शिकारी था। इस विशेष प्रजाति का जीवाश्म वर्ष 2008 में उत्तर-पूर्वी ब्राजील के भूगर्भीय इलाके से खोजा गया था। थेरोपोड मुख्य रूप से मांसाहारी डायनासोरों का समूह था, जिसमें मशहूर टी-रेक्स और वेलोसिरेप्टर जैसे खतरनाक शिकारी भी शामिल थे। जानकारों के अनुसार, जब जीवाश्म की हड्डियों के बेहद बारीक टुकड़ों की अत्याधुनिक सूक्ष्मदर्शी से जांच की गई। तो हड्डियों की नसों वाली नलिकाओं में सूक्ष्म संरचनाएं दिखाई दीं। रासायनिक विश्लेषण करने पर उनमें हीम के केमिकल सिग्नेचर स्पष्ट रूप से मिले, जिनका आकार और स्थिति पूरी तरह से लाल रक्त कोशिकाओं से मेल खाती थी। इतने लंबे कालखंड के बाद भी इस जैविक सामग्री के सुरक्षित बचे रहने के पीछे के कारणों पर विशेषज्ञों का मानना है कि डायनासोर की मृत्यु के तुरंत बाद उसका शरीर तेजी से तलछट और बिना ऑक्सीजन वाली गीली मिट्टी के नीचे दब गया था। ऑक्सीजन रहित वातावरण और सूक्ष्मजीवों की एक विशेष परत के कारण प्राकृतिक सड़न की प्रक्रिया रुक गई।

इसी दौरान हॉसमैनाइट नामक मैंगनीज ऑक्साइड खनिज ने इन जैविक संरचनाओं को चारों ओर से ढक लिया, जिससे लाल रक्त कोशिकाओं का ढांचा नष्ट होने से पहले ही खनिज के रूप में जम गया। विशेषज्ञों के अनुसार, यह खोज केवल पृथ्वी के प्राचीन जीवन के अध्ययन तक सीमित नहीं है, बल्कि अंतरिक्ष में जीवन की खोज पर भी गहरा प्रभाव डाल सकती है। यदि नाजुक जैविक अणु अत्यंत कठोर परिस्थितियों में 11 करोड़ वर्ष से अधिक समय तक बचे रह सकते हैं, तो अन्य ग्रहों पर भी प्राचीन जीवन के निशान मिलने की संभावना बढ़ जाती है। हालांकि, इस अध्ययन पर कुछ जानकारों के बीच मतभेद भी उत्पन्न हुए हैं।

अमेरिका में बढ़ेगा भारतीय सामानों का दबदबाः चीन समेत दूसरे देशों से कम लगेगा टैक्सःगोयल

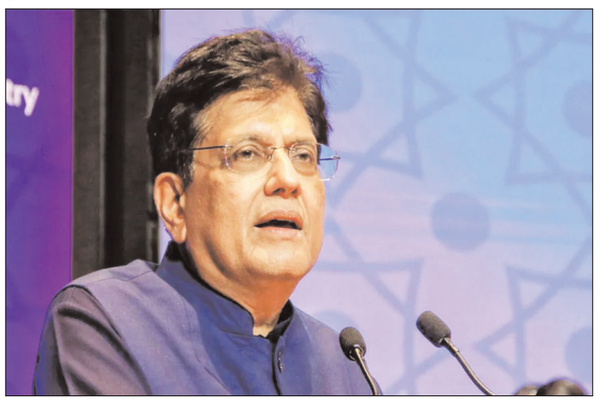
नई दिल्ली। भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक रिश्तों को लेकर एक अहम सहमति बनी है। अब अमेरिकी बाजार में भारतीय सामानों को दूसरे प्रतिस्पर्धी देशों के मुकाबले तरजीह मिलेगी। इसके तहत भारतीय उत्पादों पर उन देशों की तुलना में कम आयात शुल्क लगाया जाएगा। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने रविवार को मिस्र की राजधानी काहिरा में पत्रकारों से बातचीत के दौरान यह जानकारी दी।

ट्रंप और मोदी के बीच पहले ही बन चुकी है सहमति

पीयूष गोयल ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच कुछ महीने पहले ही इस मुद्दे पर सहमति बन गई थी। दोनों नेताओं ने व्यापक व्यापार समझौते की रूपरेखा पर सहमति बनने का एलान भी किया था। गोयल के मुताबिक, इस समझौते में यह तय हुआ था कि भारत को अमेरिकी बाजार में अपने प्रतिस्पर्धी देशों के मुकाबले कम शुल्क के साथ व्यापार करने का मौका मिलेगा।

फरवरी में तैयार हुई थी समझौते की रूपरेखा

भारत और अमेरिका ने फरवरी में द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण की रूपरेखा को अंतिम रूप दिया था। इस पर पहले ही हस्ताक्षर होने की उम्मीद थी, लेकिन अमेरिका की टैरिफ नीति में बदलाव के चलते बातचीत आगे बढ़ानी पड़ी। हाल ही में एक अधिकारी ने भी बताया था कि अमेरिका ने प्रस्तावित व्यापार समझौते के तहत भारत को दूसरे प्रतिस्पर्धी देशों के मुकाबले टैरिफ में फायदा देने का भरोसा दिया है। दोनों देश चालू वित्त वर्ष के अंत तक समझौते के पहले चरण को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। अधिकारी के मुताबिक, अभी यह देखना होगा कि अमेरिका अपना नया टैरिफ ढांचा किस तरह तैयार करता है। पहले चरण के साथ-साथ व्यापक व्यापार समझौते पर भी बातचीत जारी है।



भारतीय सामानों को वास्तव में कितना फायदा मिलेगा, यह अंतिम रूप से तय होने वाली टैरिफ व्यवस्था पर निर्भर करेगा। दरअसल, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति ट्रंप के पारस्परिक शुल्क (रेसिप्रोकल टैरिफ) को रद्द कर दिया है। यही शुल्क भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता का एक प्रमुख आधार था। इसके बाद अमेरिका ट्रेड एक्ट के प्रावधानों के तहत नए टैरिफ ढांचे के विकल्प तलाश रहा है। पीयूष गोयल इन दिनों भारत और मिस्र के बीच व्यापार तथा निवेश बढ़ाने के मकसद से दो दिवसीय दौरे पर काहिरा में हैं। उन्होंने कहा कि भारत और मिस्र की अर्थव्यवस्थाएं एक-दूसरे की प्रतिस्पर्धी नहीं, बल्कि पूरक हैं। मिस्र की कई जरूरतें भारत पूरी कर सकता है। जबकि भारत भी मिस्र से कई जरूरी चीजें मंगा सकता है। सेवा क्षेत्र में भी दोनों देश मिलकर कारोबार बढ़ा सकते हैं।

169 जिलों में यूरिया के अत्यधिक इस्तेमाल ने बढ़ाई टेंशन

कहीं देश से बाहर तो नहीं हो रहा डायवर्जन? सीएजी ने तेज की जांच

नई दिल्ली। देश के 169 जिलों में यूरिया के अत्यधिक इस्तेमाल को लेकर चर्चा तेज हो गई है। ऐसे में CAG ने फर्टिलाइजर सब्सिडी का अखिल भारतीय परफॉरमेंस ऑडिट शुरू किया है। इसका मुख्य उद्देश्य कम से कम 169 जिलों में सब्सिडी वाले यूरिया के कथित डायवर्जन (यानी तय जगह के बजाय कहीं और भेजे जाने) की जांच करना है। इसमें फर्टिलाइजर को देश के बाहर भेजे जाने की आशंका भी शामिल है। इस साल मई में शुरू हुआ यह ऑडिट 2027 के मध्य तक पूरा होने की उम्मीद है, जिसे संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किया जा सकता है। सरकार सब्सिडी वाले यूरिया पर सालाना 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक खर्च करती है। कुछ जिलों में यूरिया की खपत राष्ट्रीय और राज्य के औसत से कहीं ज्यादा है, जिसने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। ष्टत्त यूरिया सब्सिडी ढांचे की मांग और कार्यकुशलता का आकलन करेगा; यही इस ऑडिट के दायरे में भी शामिल है। जिन 169 जिलों में कथित डायवर्जन की जांच होनी है, उनमें से 149 को CAG ने शुरुआत में ही उनके खपत पैटर्न के आधार पर चुना था, जो राज्य और राष्ट्रीय औसत से अधिक था। बाद में, केंद्र सरकार की सिफारिश पर 20 और जिलों को इसमें जोड़ा गया, ताकि उनके खपत पैटर्न की भी जांच की जा सके। यह ऑडिट फर्टिलाइजर की आवाजाही, परिवहन व्यवस्था, माल ढुलाई सब्सिडी और इससे जुड़ी निगरानी और नियंत्रण प्रणाली की पड़ताल करेगा। इस व्यापक ऑडिट में विभिन्न सरकारी विभागों, जैसे GST नेटवर्क, कृषि मंत्रालय, रेलवे आदि का सहयोग लिया जाएगा। ये विभाग फर्टिलाइजर नियंत्रण प्रणाली और नियामकों (regulators) की



कार्यकुशलता के आकलन में ऑडिटरों की मदद करेंगे। हाल ही में वित्त मंत्रालय ने ई-वे बिल के आधार पर यूरिया के डायवर्जन की आशंका जताई थी, क्योंकि यह पाया गया कि ट्रक तय रास्ते के बजाय दूसरे रास्तों से जा रहे थे या कई जगहों पर रुक रहे थे। एक संसदीय समिति ने भी यूरिया के डायवर्जन, खासकर सीमावर्ती जिलों में, को लेकर चिंता जताई थी।

अधिकारियों ने बताया कि यूपी, राजस्थान, पंजाब और बिहार के सीमावर्ती जिलों से सब्सिडी वाले यूरिया को दूसरी जगहों पर भेजे जाने (डायवर्जन) की खबरों ने इस बात पर भी संदेह पैदा कर दिया है कि कहीं इसे देश के बाहर तस्करी करके तो नहीं भेजा जा रहा है। यूरिया की अत्यधिक खपत के लिए जिन जिलों की जांच की जा रही है, उनमें सबसे ज्यादा 37 जिले यूपी में हैं। इसके बाद बिहार और तमिलनाडु में 16-16 जिले, और पंजाब तथा गुजरात में 14-14 जिले शामिल हैं। बाद में जांच के दायरे में लाए गए 20 जिले कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से हैं।

भारत में यूरिया की कुल खपत सालाना लगभग 400 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है। इसमें से 100 LMT से अधिक का आयात किया जाता है।

घरेलू उत्पादन के लिए भी बड़ी मात्रा में आयातित LPG की जरूरत होती है, क्योंकि यूरिया बनाने की कुल लागत में 90 फीसदी हिस्सा इसी ईंधन का होता है। एक अधिकारी ने बताया कि सब्सिडी वाले यूरिया की अत्यधिक खपत से सरकारी खजाने पर सब्सिडी का बोझ बढ़ता है और आयात पर हमारी निर्भरता भी बढ़ती है। इसके अलावा, इससे ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन भी बढ़ता है। अधिकारी ने कहा कि चूंकि कृषि कार्यों में इस्तेमाल होने वाले यूरिया पर हर जगह सब्सिडी मिलती है, इसलिए लंबे समय से इसकी एक बड़ी मात्रा को गैर-कृषि क्षेत्रों में भेजा जाता रहा है। %टेक्निकल ग्रेड% यूरिया का इस्तेमाल रेजिन, गोंद, प्लाईवुड बनाने, क्रॉकरी (बर्तन) निर्माण, पशु आहार और व्यावसायिक विस्फोटकों (एक्सप्लोसिव्स) के उत्पादन में एक मुख्य कच्चे माल के रूप में किया जाता है।

छत्तीसगढ़ शासन
सत्यमेव जयते

किसानों के सम्मान और समृद्धि का उत्सव



श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

धान खरीदी उत्सव 2026-27

15 नवंबर 2026 से धान खरीदी प्रारंभ

प्रदेश के सभी **3,100 उपार्जन केंद्रों पर होगी खरीदी**

₹3,100 प्रति क्विंटल
की दर से धान खरीदी

₹13,839 प्रति एकड़
की दर से आदान सहायता

21 क्विंटल से कम
धान बेचने पर भी मिलेगी
पूरी आदान सहायता राशि

25.49 लाख कृषक एग्रीस्टैक पोर्टल पर पंजीकृत
कृषकों को **नहीं कराना होगा दोबारा पंजीयन**

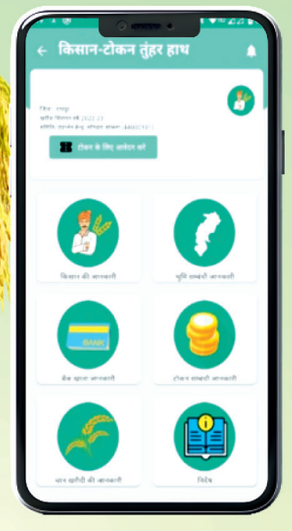
कृषक कल्याण की
विभिन्न योजनाओं से
₹ 1.50 लाख करोड़
से अधिक की राशि अंतरित

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि
25 लाख किसान
लाभान्वित



बायोमेट्रिक प्रणाली से
पारदर्शी खरीदी व्यवस्था

तुंहर टोकन ऐप से
घर बैठे टोकन व्यवस्था



24x7
उपलब्ध

संवाद-49792/157

छत्तीसगढ़ जनसंपर्क
Visit us : /ChhattisgarhCMO /DPRChhattisgarh www.dprcg.gov.in
हमसे जुड़ने के लिए QR स्कैन करें

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.